सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 02, नई दिल्ली । शुक्रवार, 15 मार्च 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

खुद पर विश्वास करें निश्चित है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके कदम चूमेगा।

03 जेएनयू स्टूडेंट यूनियन इलेक्शनः वाम संगठनों में प्रत्याशी के लिए मंथन जारी
06 पर्यटन प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बने हिमाचल
08 भाजपा जिलाध्यक्ष मेवाड़ा ने की विधानसभा प्रभारियों की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के दो कॉरिडोर का किया शिलान्यास

पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर के निर्माण की गुरुवार को आधारशिला रखी। केंद्र सरकार ने लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक तक दो नए मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी थी। लगभग 8400 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले दोनों कॉरिडोर का काम मार्च 2029 तक पूरा हो जाएगा। दोनों कॉरिडोर में कुल 18 स्टेशन होंगे।

संजय बाटला

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के दो कॉरिडोर का गुरुवार को शिलान्यास किया। इस कॉरिडोर में पहला लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक है और दूसरा इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक है। दोनों कॉरिडोर की लंबाई करीब बीस किमी की होगी। इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए मोदी कैबिनेट ने बुधवार को ही मंजूरी दे दी थी।

बता दें, केंद्र सरकार ने लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक तक दो नए मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण को बुधवार को मंजूरी दे दी थी। लगभग 8400 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले दोनों कॉरिडोर का काम मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क बढ़ेगा और लोगों की आवाजाही की परेशानी दूर होगी।

लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर

1. यह कॉरिडोर सिल्वर, मैजेंटा, पिंक और वॉयलेट लाइन को कनेक्ट करेगा।
2. यह पूरी तरह एलिवेटेड होगा और इसमें कुल 8 स्टेशन होंगे।

इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर

1. ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन होगा
2. इसमें 11.34 किलोमीटर अंडरग्राउंड लाइन जबकि 1.02 किलोमीटर एलिवेटेड होगा। इसमें 10 स्टेशन होंगे।
3. इसमें रेड, येलो, एयरपोर्ट लाइन, मैजेंटा, वॉयलेट और ब्लू लाइन के लिए इंटरचेंज किया जा सकेगा।
4. इस कॉरिडोर के जरिए बहादुरगढ़ तक कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी।

नए कॉरिडोर में प्रस्तावित स्टेशन

लाजपत नगर से साकेत जी-ब्लॉक कॉरिडोर के स्टेशनः लाजपत नगर, एंड्रयूज गंज, ग्रेटर कैलाश - 1, चिराग दिल्ली, पुष्पा भवन, साकेत जिला केंद्र, पुष्प विहार, साकेत जी - ब्लॉक।

इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के स्टेशनः इंद्रलोक, दया बस्ती, सराय रोहिल्ला, अजमल खान पार्क, नबी करीम, नई दिल्ली, एलएनजेपी अस्पताल, दिल्ली गेट, दिल्ली सचिवालय, इंद्रप्रस्थ।

राम मंदिर स्मृति चिह्न देकर पीएम का स्वागत

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित पीएम स्वनिधि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राम मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि महोत्सव हमारे आसपास रहने वाले उन लोगों को समर्पित है जिनके बिना हमारी रोजमर्रा के जीवन कि कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

विशेष परिवहन आयुक्त का डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को व्यवसायिक वाहन कार्य की शाखाओं से हटाना कितना तर्कसंगत

संजय बाटला

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय भारत की एक खंडपीठ **जस्टिस पीएस नरसिम्हा ओर जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, स्थायी या बारहमासी प्रकृति का कार्य किसी संविदा कर्मचारी से नहीं कराया जा सकता है। इसे नियमित-स्थायी कर्मचारी को ही करना चाहिए।** पर साथ ही फैसले में कहा **एक साल या उससे अधिक समय तक किसी विभाग में किसी एक कार्य पर कार्यरत कांट्रेक्ट कर्मचारी को सरकार स्थायी कर्मचारी माने और बनाए** सुप्रीम कोर्ट

बारहों महीने काम के लिए रखे श्रमिकों को संविदा कर्मचारी नहीं मान सकते', सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी;

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बारहों महीने या स्थायी प्रकृति के काम करने के लिए रखे गए श्रमिकों को सिर्फ नियमितीकरण के लाभ से वंचित करने के लिए अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के तहत अनुबंध श्रमिकों के रूप में नहीं माना जा सकता है। शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स के 32 में से उन 13 श्रमिकों को नियमित करने का आदेश दिया जिन्हें अनुबंध श्रमिक मानकर नियमित नहीं किया गया था।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा ओर जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, स्थायी या बारहमासी प्रकृति का कार्य किसी संविदा कर्मचारी से नहीं कराया जा सकता है। इसे नियमित-स्थायी कर्मचारी को ही करना चाहिए। यह मामला कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स की ओर से नियोजित कुल 32 श्रमिकों में से 13 श्रमिकों के गैर-नियमितीकरण से जुड़ा है। इन्हें बारहमासी कार्य करते समय अनुबंध श्रमिक माना गया था। कंपनी ने सिर्फ 19 श्रमिकों को नियमित किया था। 13 श्रमिकों को इस आधार पर नियमित करने से इन्कार कर दिया गया था कि वे जो काम करते हैं वह आकस्मिक है और निरंतर-बारहमासी नहीं, जिससे वे अनुबंध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970) के तहत नियमित होने के लिए अयोग्य हो गए।

ट्रिब्यूनल ने भी ठहराया था कर्मचारियों को नियमितीकरण का हकदार

केंद्र के हस्तक्षेप के बाद, मामला केंद्रीय औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण को भेजा गया। ट्रिब्यूनल ने भी 13 श्रमिकों के काम को नियमित हुए 19 श्रमिकों के समान माना। इसलिए उन्हें अन्य 19 श्रमिकों को प्रदान की गई बकाया मजदूरी और नौकरियों के नियमितीकरण का हकदार बताया। ट्रिब्यूनल ने माना कि बंकर के नीचे, रेलवे साइडिंग में गंदगी हटाने का काम और 13 श्रमिकों की ओर से (बंकर में) ढलानों का संचालन नियमित और बारहमासी प्रकृति का है। हाईकोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा था जिसके बाद महानदी कोलफील्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

ट्रिब्यूनल के पास श्रमिकों को स्थायी दर्जा देने की शक्ति नहीं

महानदी कोलफील्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल के पास श्रमिकों को स्थायी दर्जा देने की कोई शक्ति नहीं है। क्योंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी/श्रमिक संघ के बीच हुआ समझौता सभी पक्षों पर बाध्यकारी है। इस तर्क को खारिज करते हुए पीठ ने 13 श्रमिकों को स्थायी दर्जा देने के केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा और उन्हें न्यायाधिकरण के फैसले के प्रभाव से पिछला वेतन प्रदान करने का निर्देश दिया।

अब प्रश्न यह उठता है कि परिवहन विभाग द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को बारहों महीने या स्थायी प्रकृति के काम करने के लिए रखा गया था और सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया की खंडपीठ का मानना और कहना है की स्थायी प्रकृति के लिए रखे गए श्रमिकों को सिर्फ नियमितीकरण के लाभ से वंचित करने के लिए अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के तहत अनुबंध श्रमिकों के रूप में नहीं माना जा सकता है तो विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को परिवहन विभाग में व्यवसायिक वाहनों की कार्य शाखाओं में कार्य ना करने देने के पीछे कोन सा कानून/ नियम का उपयोग कर आदेश पारित किए वह भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जगह बिना अन्य स्टाफ को शाखाओं में भेजे?

डीजल की टैक्सी बसें ग्रेप सिस्टम से परमानेंट बाहर करने के लिए हम इलेक्शन के बाद बड़ा आंदोलन करेंगे

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन काफी समय से टैक्सी बसों के ट्रांसपोर्टर्स/मालिकों के हक़ के लिए काम कर रहीं हैं.

जैसा की एक डर का माहौल टैक्सी बस वालो के मन में था की BS 3/4 डीजल टैक्सी बसें सरकार या CAQM परमानेंट बंद कर रहें हैं. तो ये CAQM के इस पत्र से साफ हैं की जब तक BS 3/4 डीजल टैक्सी बसों की लाइफ हैं वो उतने साल ही चलेंगी और इस का फायदा डीजल BS 3/4 के सारे टैक्सी- बसों, टेम्पो ट्रेवलर के दिल्ली एनसीआर के ट्रांसपोर्टरस /मालिकों के अलावा पूरे भारत के ट्रांसपोर्टर्स को फायदा मिला हैं जिनकी ये गाड़ियाँ दिल्ली एनसीआर में आती जाती रहती हैं. इसके लिए हमने लगातार धरने प्रदर्शन किये और लगातार पत्रों और अखबारों/ मीडिआ के द्वारा ट्रांसपोर्टर्स की आवाज को बुलंद किया. अभी जब भी प्रदूषण बढ़ेगा और ग्रेप 3/4 लगेगा तो हमारी BS 3/4 डीजल की टैक्सी बसों की एंट्री दिल्ली एनसीआर में बंद रहेंगी. हमारी डीजल की टैक्सी बसें ग्रेप सिस्टम से परमानेंट बाहर करने के लिए हम इलेक्शन के बाद बड़ा आंदोलन करेंगे.

हमें अपना संख्या बल और एकता बनानी हैं.

अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो केंद्र /राज्य सरकारे हमारी सीएनजी डीजल दोनों तरह की टैक्सी बसों को बंद करने के लिए तैयार बैठी हैं. 2026 तक डीजल और 2028 तक सीएनजी सारी टैक्सी बसों को बंद करके सिर्फ इलेक्ट्रिक टैक्सी बसें ही सरकार चलवाना चाहती हैं.

इसलिए सारे भाई मजबूती से अपनी एकता बनाये.

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन.

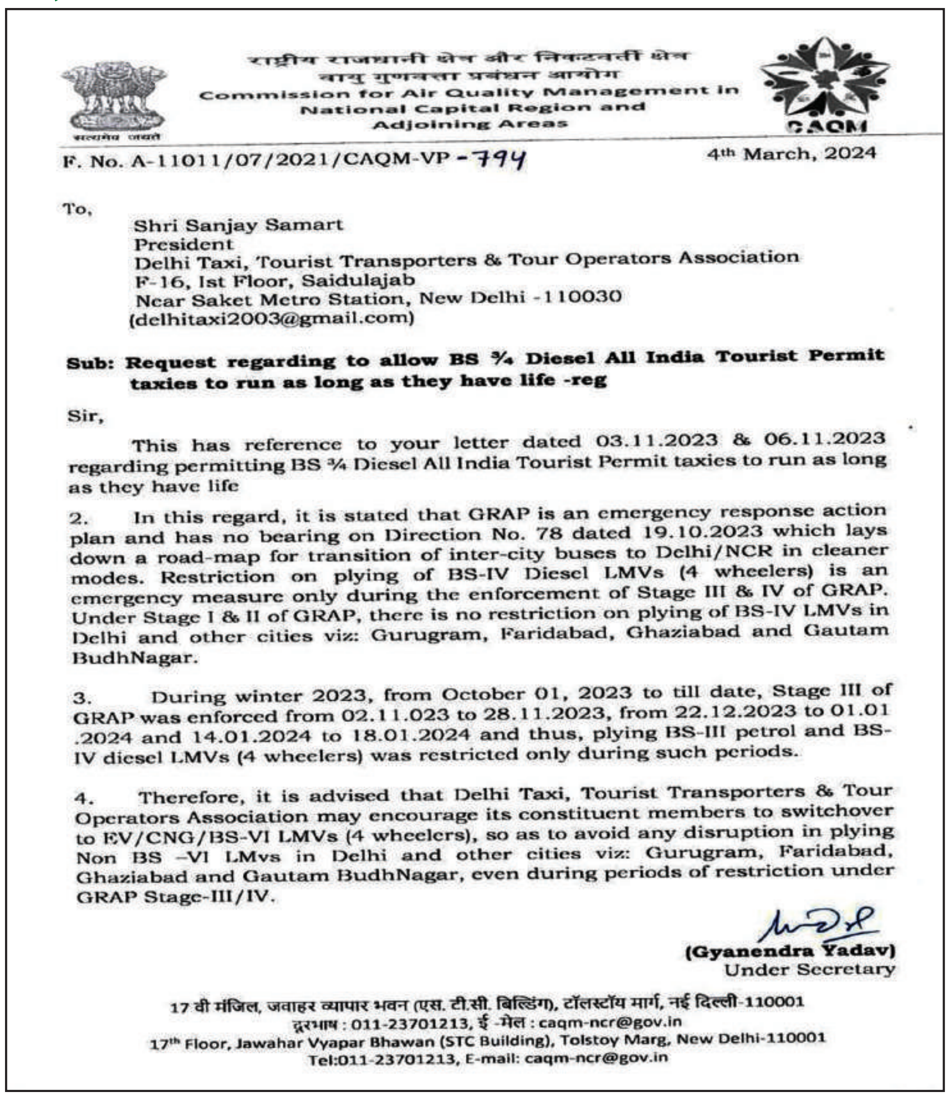

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas
सत्यमेव जयते
CAQM

F. No. A-11011/07/2021/CAQM-VP -794   4th March, 2024

To,
Shri Sanjay Samart
President
Delhi Taxi, Tourist Transporters & Tour Operators Association
F-16, Ist Floor, Saidulajab
Near Saket Metro Station, New Delhi -110030
(delhitaxi2003@gmail.com)

Sub: Request regarding to allow BS ¾ Diesel All India Tourist Permit taxies to run as long as they have life -reg

Sir,

This has reference to your letter dated 03.11.2023 & 06.11.2023 regarding permitting BS ¾ Diesel All India Tourist Permit taxies to run as long as they have life

2. In this regard, it is stated that GRAP is an emergency response action plan and has no bearing on Direction No. 78 dated 19.10.2023 which lays down a road-map for transition of inter-city buses to Delhi/NCR in cleaner modes. Restriction on plying of BS-IV Diesel LMVs (4 wheelers) is an emergency measure only during the enforcement of Stage III & IV of GRAP. Under Stage I & II of GRAP, there is no restriction on plying of BS-IV LMVs in Delhi and other cities viz: Gurugram, Faridabad, Ghaziabad and Gautam BudhNagar.

3. During winter 2023, from October 01, 2023 to till date, Stage III of GRAP was enforced from 02.11.023 to 28.11.2023, from 22.12.2023 to 01.01.2024 and 14.01.2024 to 18.01.2024 and thus, plying BS-III petrol and BS-IV diesel LMVs (4 wheelers) was restricted only during such periods.

4. Therefore, it is advised that Delhi Taxi, Tourist Transporters & Tour Operators Association may encourage its constituent members to switchover to EV/CNG/BS-VI LMVs (4 wheelers), so as to avoid any disruption in plying Non BS -VI LMvs in Delhi and other cities viz: Gurugram, Faridabad, Ghaziabad and Gautam BudhNagar, even during periods of restriction under GRAP Stage-III/IV.

(Gyanendra Yadav)
Under Secretary

17 वी मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस. टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23701213, ई -मेल : caqm-ncr@gov.in
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg, New Delhi-110001
Tel:011-23701213, E-mail: caqm-ncr@gov.in

मोटर वाहन से सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस उपचार, सरकार ने शुरू किया पायलट

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत सरकार मोटर वाहनों के इस्तेमाल के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू कर रही है। सरकार का यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी जनादेश के अनुरूप है। सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि यह पायलट कार्यक्रम, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में विकसित किया गया है। इसे चंडीगढ़ में शुरू किया जा रहा है और इसका मकसद दुर्घटना के गोल्डन आवर्स (स्वर्णिम घंटे) सहित, सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को समय पर चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने के लिए एक इकोसिस्टम स्थापित करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) पुलिस, अस्पतालों, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) के समन्वय से पायलट कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

पायलट कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह है:

दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार के हकदार पीड़ित।

सड़क की किसी भी श्रेणी पर मोटर वाहन के इस्तेमाल के कारण होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) पैकेजों को ट्रॉमा (मल्टीपल चोट) के मामलों के लिए शामिल किया जा रहा है।

उपचार प्रदान करने के लिए अस्पतालों द्वारा किए गए दावों की राशि मोटर वाहन दुर्घटना निधि से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

कार्यक्रम को एक आईटी प्लेटफॉर्म के जरिए लागू किया जाएगा। जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-डीएआर एप्लिकेशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की लेन-देन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) की कार्यक्षमताओं को जोड़ता है।

[redacted] आईटीओ, दिल्ली गेट, दरियागंज और सराय काले खां के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-24 समेत अन्य स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए।

किसानों की महापंचायत से दिल्ली में भीषण जाम, सड़कों पर रेंगते रहे वाहन; कई जगह ट्रैफिक डायवर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत के कारण दिल्ली भीषण जाम देखने को मिला। कई सड़कों पर घंटों तक वाहनों रेंगते रहे। भारी ट्रैफिक जाम को देखते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई। जिसमें लोगों को कई रास्तों से बचने की सलाह दी गई। साथ ही कई रास्ते पर ट्रैफिक डायवर्जन के बारे में बताया गया।

नई दिल्ली। किसानों के महापंचायत के कारण दिल्ली के कई रास्ते में भारी ट्रैफक जाम रहा। गुरुग्राम दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों ने महापंचायत का एलान किया था। महापंचायच में कई राज्यों से किसान जुटे, जिसके चलते मध्य दिल्ली और सराय काले खां में ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो गई। कई सड़कों पर भारी जाम देखने को मिला।

वाहनों की लंबी कतार

आईटीओ, दिल्ली गेट, दरियागंज और सराय काले खां के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-24 समेत अन्य स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए। दिल्ली के सराय काले खां में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम रहा और वाहनों की लंबी लाइनें लगी रहीं। इस दौरान यात्रियों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन आवागमन धीरे-धीरे जारी रहा।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के अलावा चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी पर यातायात का दबाव रहा। सुबह सात बजे से लेकर 11 बजे के बीच ट्रैफिक का दबाव रहा। दिल्ली के ताजपुर मोड़ से लेकर सोनीपत के जाटी मोड़ कुंडली तक वाहनों की 3 किमी लंबी लाइन देखने को मिली। वहीं, कुंडली बॉर्डर पर किसानों के वाहनों की जांच के बाद दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है। इससे कुंडली बॉर्डर पर भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

इन मार्गों से बचने की सलाह

जाम को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ट्रैफिक नियमों में डायवर्जन के बारे में बताया गया। ट्रैफिक एडवाइजरी में जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बाराखंभा रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, टॉल्स्टॉय मार्ग, आसफ अली रोड, जय सिंह रोड, स्वामी विवेकानंद मार्ग, संसद मार्ग, नेता जी सुभाष मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, मिंटो रोड, अशोक रोड, महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर, कनॉट सर्कस, भवभूति मार्ग, डीडीयू मार्ग और चमन लाल मार्ग से बचने की सलाह दी गई।

कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट

वहीं, दिल्ली गेट, मीर दर्द चौक, अजमेरी गेट चौक, गुरु नानक चौक, कमला मार्केट रोड, पहाड़गंज चौक, झंडेवालान चौराहे, महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर पर बाराखंभा रोड से गुरु नानक चौक, जनपथ रोड पर ट्रैफिक डायवर्ट करने की बात कही गई।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

मध्य प्रदेश की सुपरहिट लाडली बहन योजना: 21 साल से अधिक आयु है तो ले सकती हैं लाभ, मगर एक बड़ी शर्त

इन दिनों महिलाओं और उनके वित्त से जुड़े मसलों पर सरकारी योजनाओं से जुड़ी सीरीज चलाई हुई है, जो खास महिलाओं के लिए हैं. ऐसी स्कीमें जिनमें सरकार की ओर से महिलाओं को छूट व सुविधाएं दी जाती हैं, उनके सशक्तीकरण के उपाय किए जाते हैं, के बारे में हम आपको बताते हैं. आज जानिए मध्य प्रदेश सरकार की Ladli Bahan Yojana के बारे में सबकुछ...

मध्य प्रदेश की सुपरहिट और लोकप्रिय योजना का नाम है लाडली बहन योजना. इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वालम्बन प्रदान करना और उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाना रहा है. 28 जनवरी 2023 को शुरू की गई इस योजना में जहां पहले 1 हजार रुपये प्रति माह दिए जाते थे, वहीं इन्हें बढ़ाकर अब 1250 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. मध्य प्रदेश सरकार की ओर शुरू की गई इस योजना का लाभ किसे मिलता है और कब मिलता है, आप इसके लिए कैसे और कहां अप्लाई कर सकती हैं, किन जरूरी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना होगा, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए आगे पढ़ें'

लाडली बहन योजना में क्या मिलता है और किसे मिलता है

सरकार की यह योजना गरीबों के लिए है. मध्य प्रदेश की वह हर महिला जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है वे इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं और उनके डीबीटी ऐनेब्ल्ड बैंक खाते में 1000/- रुपये प्रति माह की राशि का भुगतान सरकार की ओर से किया जाता है. पहले उम्र सीमा 23 साल थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 21 साल कर दिया गया है. महिलाओं और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप यहां क्लिक कर सकती हैं.

आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 01 जनवरी को 23 वर्ष पूर्ण और 60 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए. योजना का लाभ हर वर्ग की- सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति- महिला आवेदन कर सकती है. शर्त यह है कि आवेदकों को विवाहित होना चाहिए जिसमें विधवा, तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं.

लाडली बहन योजना: किसे नहीं मिलता लाभ

वे महिलाएं योजना की लाभार्थी नहीं हो सकतीं जिनकी संयुक्त स्व-घोषित (जॉइंट सेल्फ डिक्लेयर्ड) वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है. या, महिला खुद या महिला के परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स पेयर है. या फिर, भारत सरकार या राज्य सरकार में सरकारी नौकरी कर रहा है या फिर पेंशनप्राप्त कर रहा है. इस बारे में अधिक जानकारी केको लिए आप मध्य प्रदेश सरकार की वेब साइट पर लॉग इन कर सकती हैं- https://cmladlibahna.mp.gov.in/ स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही लड़कियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही महिला को विवाहित कैटेगरी में होना चाहिए.

कैसे करें अप्लाई, क्या दस्तावेज चाहिए

आप इसके लिए ऐप्लिकेशन फॉर्म ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, कैंप ऑफिस में मिलेंगे. फोटोग्राफ के साथ अप्लाई करना होगा. ये फॉर्म भरने के बाद लाडली बहना पोर्टल और ऐप में जमा किये जाएंगे. आवश्यक दस्तावेज के तौर पर परिवार और परिवार के सदस्यों की समग्र आईडी, आधार कार्ड और समग्र पंजीकृत मोबाइल नंबर चाहिए.

5 मामलों में फौलादी होते हैं मां का दूध पीने वाले बच्चे, फेल है फॉर्मूला मिल्क या गाय का दूध, ब्रेस्ट फीडिंग है अद्भुत

अगर आप नए-नए मां बाप बनने जा रहे हैं तो आपके बेबी के लिए ब्रेस्टफीडिंग यानि मां का दूध और फॉर्मूला या गाय भैंस के दूध को लेकर ये जानकारी बहुत काम की है. स्तनपान आपके बच्चे के दिमाग और शरीर को फौलाद बनाता है.

छोटे और नवजात बच्चों के लिए मां का दूध संपूर्ण आहार होता है, ये बात आपने भी सुनी होगी. बावजूद इसके बहुत सारी माएं किन्हीं कारणों से बच्चे को कम से कम 6 महीने तक भी स्तनपान नहीं करातीं. ऐसे बच्चे या तो फॉर्मूला मिल्क फीडिंग करते हैं या गाय-भैंस के दूध से गुजारा करते हैं. लेकिन एक बार अगर आप मां के दूध के फायदे जान लेंगे तो कभी भी नवजात बच्चों के लिए मां के दूध की जगह कोई और विकल्प नहीं चुनेंगे क्योंकि ब्रेस्टफीडिंग करने वाले बच्चे फॉर्मूला या गाय-भैंस का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग से भी फौलादी होते हैं.

हैदराबाद की जानी मानी पीडियाट्रिशियन डॉ. शिवरंजनि संतोष नए-नए बनने वाले माता-पिता को यही बातें पिछले कई सालों से समझा रही हैं. जगह-जगह वर्कशॉप कर न केवल मांओं को बच्चों को ब्रेस्टफीड कराने का तरीका बता रही हैं, बल्कि इसके फायदे भी गिना रही हैं. आइए जानते हैं उनसे स्तनपान को लेकर जरूरी बातें.

कितने साल तक माएं कराएं ब्रेस्टफीड?

अगर आपको लगता है कि बच्चों को स्तनपान कराना 6 महीने तक जरूरी है, क्योंकि ऐसी सरकारी गाइडलाइंस हैं और डॉक्टर भी सलाह देते हैं तो यह पर्याप्त जानकारी नहीं है. डॉ. शिवरंजनि कहती हैं कि बच्चे को 6 महीने तक ब्रेस्टफीड कराकर रोकना नहीं चाहिए. कई स्टडीज के एनालिसिस के आधार पर आइडियली बच्चे को 2 साल या उससे ऊपर भी स्तनपान कराना अच्छा होता है. जो बच्चा मां का दूध जितना लंबी अवधि तक पीता है, उसके फायदे उसको मिलते हैं.

कितनी बार बच्चे को पिलाएं दूध?

डॉ. संतोष कहती हैं कि बच्चे को जितनी जरूरत हो, उतनी बार दिन में दूध पिलाएं. ऐसा नहीं है कि इसका कोई टाइम फ्रेम होता है. हालांकि फिर भी मांओं को समझाने के लिए 6 महीने तक हर दो से 3 घंटे में स्तनपान कराना चाहिए.

40 की उम्र के बाद महिलाएं जरूर कराएं 2 टेस्ट, मौत का खतरा होगा कम, डॉक्टर से जानें 5 बड़ी बातें

40 साल की उम्र के बाद महिलाएं कई हॉर्मोनल बदलावों से गुजरती हैं और कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में महिलाओं को 40 की उम्र पार करने के बाद सेहत को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए और नियमित स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए.

उम्र बढ़ने के साथ सेहत से जुड़ी समस्याएं पैदा होने लगती हैं. खासतौर से महिलाओं को बढ़ती उम्र में ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है. 40 साल के बाद महिलाओं को अपनी सेहत को लेकर बेहद सावधान होने की जरूरत होती है. इस दौरान अगर वे हेल्थ को लेकर जरूरी कदम उठा लें, तो कई जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है. दुनियाभर में कैंसर महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. कुछ तरह के कैंसर महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करते हैं. इनसे बचने के लिए वैक्सीन से लेकर स्क्रीनिंग कराने की जरूरत होती है. डॉक्टर्स की मानें तो महिलाओं को कैंसर से बचने के तरीके जान लेने चाहिए, ताकि इस जानलेवा बीमारी से बचा जा सके.

नई दिल्ली के मिनिमल एक्सेस स्मार्ट सर्जरी हॉस्पिटल (MASSH) के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉ. सचिन अम्बेकर के मुताबिक महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन होता है. इसके बाद सर्वाइकल कैंसर का नंबर आता है. ये दोनों कैंसर महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के आंकड़ों के अनुसार, हर साल 6.85 लाख से ज्यादा महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर और 3.42 लाख महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो जाती है. कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन सही कदम उठाने से कैंसर से बचाव किया जा सकता है. सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है और 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन लगाकर इस कैंसर से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है. इसके अलावा अच्छी आदतें अपनाने से कैंसर का खतरा कम हो सकता है.

डॉ. सचिन अम्बेकर की मानें तो कैंसर का जल्दी पता लगाना और जांच करवाना बहुत ज़रूरी है. अगर ब्रेस्ट, सर्वाइकल या ओवरी समेत किसी भी कैंसर का शुरुआती स्टेज में पता चल जाए और इलाज शुरू कर दिया जाए, तो उसे ठीक करने की संभावना काफी बढ़ जाती है. कैंसर होने के कई कारण हो सकते हैं. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है. अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर हुआ है, तो आपके लिए भी खतरा ज्यादा होता है. मोटापा, धूम्रपान और शराब पीने की आदत भी कैंसर का कारण बन सकती है. खासतौर पर स्तन कैंसर में अगर मां या नानी को ये बीमारी हुई है, तो उस महिला को भी खतरा ज्यादा हो सकता है. ऐसा खास जीन बीआरएसी1 या बीआरएसी2 में हुए में म्यूटेशन या बदलाव के कारण भी हो सकता है. यह जीन माता-पिता से बच्चों को मिलते हैं.

डॉक्टर कहते हैं कि सभी महिलाओं को 40 की उम्र के बाद ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की जांच जरूर करवानी चाहिए. अगर किसी महिला को ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस हो रही हो, तो उसे तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर जांच करवानी चाहिए. अगर किसी तरह की अबनॉर्मल ब्लीडिंग महसूस हो, तो सर्वाइकल कैंसर की जांच करवानी चाहिए. इसके अलावा शरीर के किसी भी अंग में कोई परेशानी महसूस हो, तो इसे लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट करना चाहिए. आमतौर पर महिलाओं को कैंसर का खतरा 15 से 65 साल की उम्र में ज्यादा होता है. ऐसे में शुरू से ही महिलाओं को सेहत को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए. हेल्दी फूड्स से भरपूर डाइट लेनी चाहिए और खुद को एक्टिव रखना चाहिए. इससे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकेगी।

राजनीति में नारी की 'कागजी' भागीदारी... आधी आबादी के सच से रूबरू कराता ये लेख

आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले तक दिल्ली एनसीआर की 13 लोकसभा सीटों में से केवल दिल्ली की एक सीट पर ही महिला सांसद थीं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी को अलग कर दिया जाए तो अन्य एक भी सीट पर महिला सांसद नही थीं। अब लोकसभा में नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज और पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत को लोकसभा का टिकट भाजपा ने दी है। राजनीति में महिलाओं की दशा बताने के लिए दिल्ली-एनसीआर का उदाहरण ही काफी है।

यूं तो देश की महिलाएं राजनीति के उच्च शिखर तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन उन्हें राजनीति में वह सम्मान आज तक नही मिल सका है, जिसकी वह हकदार हैं। और तो और देश की राजधानी में जहां देश की संसद है और जहां से देश की सरकार चलती उस दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति अच्छी नहीं है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले तक दिल्ली एनसीआर की 13 लोकसभा सीटों में से केवल दिल्ली की एक सीट पर ही महिला सांसद थीं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी को अलग कर दिया जाए तो अन्य एक भी सीट पर महिला सांसद नही थीं। अब लोकसभा में नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज और पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत को लोकसभा का टिकट भाजपा ने दी है। राजनीति में महिलाओं की दशा बताने के लिए दिल्ली-एनसीआर का उदाहरण ही काफी है।

बेशक महिलाओं को लेकर 1998 से लंबित कानून को संसद से पास करा दिया गया है, जिसमें महिलाओं की 33 प्रतिशत की हिस्सेदारी की बात की गई है, लेकिन राजनीति में महिलाओं स्थिति अभी भी ठीक नहीं है।

दिल्ली-एनसीआर में कितनी महिला प्रत्याशी?

एनसीआर में 13 लोकसभा सीटें आती हैं। दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा शुरू हो गई है, इसमें से गठबंधन में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने सात में से अपने हिस्से की चार सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, मगर एक भी महिला को टिकट नहीं दिया है। जबकि भाजपा ने घोषित किए गए 7 सीटों के प्रत्याशियों में से दो महिलाओं को टिकट दिया है।

कांग्रेस गठबंधन में बची हुई तीन सीटों में से किसी सीट पर महिला प्रत्याशी उतारेगी, अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एनसीआर क्षेत्र की अन्य सीटों पर भी किसी दल द्वारा महिलाओं को उतारे जाने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीति में कागजों में ज्यादा, जमीन पर कम हिस्सेदारी है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी।

> एक समस्या यह भी है कि भारत एक गहन पितृसत्तात्मक समाज है और महिलाओं को प्रायः पुरुषों से हीन माना जाता है। यह मानसिकता समाज में गहराई तक समाई हुई है और महिलाओं की राजनीति में नेतृत्व एवं भागीदारी की क्षमता के संबंध में लोगों की सोच को प्रभावित करती है। यह एक अच्छी शुरुआत है कि अब इस दिशा में गंभीरता से सोचा जाने लगा है।

महिलाओं की भागीदारी में भारत पीछे!

अपेक्षा की जाती है कि भारत वर्ष 2030 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की 1.6% की तुलना में 6.8% की दर से विकास करेगी, लेकिन भारत के इस आशाजनक आर्थिक विकास के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अनुरूप गति नहीं पा सकी है।

हाल के समय में भारतीय चुनावों में मतदान के मामले में एक आश्चर्यजनक बदलाव दिखाई पड़ा है। देश में महिला मतदाताओं द्वारा मतदान में वृद्धि हुई है

इस परिदृश्य में राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की राह में मौजूद बाधाओं को दूर करना समय की मांग है। लैंगिक समता प्राप्त करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का समान अवसर मिले, नीति निर्माताओं, नागरिक समाज संगठनों और आम जनता को मिलकर कार्य करना होगा।

17वीं लोकसभा में कितनी प्रतिशत महिलाएं?

अंतर-संसदीय संघ द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, भारत में 17वीं लोकसभा में कुल सदस्यता में महिलाएं मात्र 14.44% का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत निर्वाचन आयोग की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएं संसद के सभी सदस्यों के मात्र 10.5% का प्रतिनिधित्व करती हैं।

राज्य विधानसभाओं के मामले में महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व औसतन 9% है। इस संबंध में भारत की रैंकिंग में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। हैरानी की बात तो यह है कि यह वर्तमान में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है।

महिलाओं को दिए जाते हैं कम मौके

राजनीतिक जानकारों की मानें तो महिलाओं को राजनीतिक दलों में प्रायः कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिससे उनके लिए अपने दलों में विभिन्न पदों से गुजरते हुए आगे बढ़ना और चुनाव के लिए दल का नामांकन प्राप्त करना कठिन हो जाता है। प्रतिनिधित्व की इस कमी को राजनीतिक दलों के भीतर मौजूद लैंगिक पूर्वाग्रह और इस धारणा का परिणाम माना जा सकता कि महिलाएं पुरुषों की तरह चुनाव जीतने योग्य नहीं होतीं।

एक समस्या यह भी है कि भारत एक गहन पितृसत्तात्मक समाज है और महिलाओं को प्रायः पुरुषों से हीन माना जाता है। यह मानसिकता समाज में गहराई तक समाई हुई है और महिलाओं की राजनीति में नेतृत्व एवं भागीदारी की क्षमता के संबंध में लोगों की सोच को प्रभावित करती है। यह एक अच्छी शुरुआत है कि अब इस दिशा में गंभीरता से सोचा जाने लगा है।

नगर निगम में महिलाएं बुलंदी पर तो विधानसभा में... ?

आज दिल्ली नगर निगम में आरक्षण के कारण 50 प्रतिशत महिला पार्षद हैं। यह बात और है कि कई महिलाओं की सीटों को उनके परिवार के लोग देखते हैं, मगर उन्हें सम्मान मिला है। आज दिल्ली में महापौर के पद पर महिला हैं। गाजियाबाद में भी महापौर पद पर महिला हैं।

आरक्षण नहीं होने पर दिल्ली विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत तो क्या 20 प्रतिशत भी नहीं है। दिल्ली विधानसभा में 12 प्रतिशत महिलाओं ही हिस्सेदारी है। ऐसे में यहां भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी नजर आएगी।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर हम समग्र बात करें तो भारत के इतिहास में आधुनिक काल ही अधिक महत्त्वपूर्ण है। महिलाएं भारत की जनसंख्या का करीब आधी आबादी हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षाकृत देश की आर्थिक संपन्नता का कम लाभ मिला है।

अधिकांश महिलाओं के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण उन पर महामारी का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। देश भर से ऐसी कई मजबूत औरतों की कहानियां सामने आईं, जिन्होंने अपने घरों से बाहर निकालकर साहस और हिम्मत दिखाते हुए अपने समुदाय की सहायता की।राजनीति में अपना मुकाम हासिल किया है।

चुनाव से जुड़ी और हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए यहां क्लिक करें

महिलाओं को प्रेरित करती इनकी कहानियां

ये कहानियां दूसरों को आगे बढ़ने के लिए उम्मीद और प्रोत्साहन देती हैं। इनमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, मैडम बीकाजी कामा, कस्तूरबा, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित ने महत्त्वपूर्ण योगदान किया।

स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में इंदिरा गांधी नंदिनी सत्पथी, मोहसिना किदवई, गिरिजा व्यास, सुषमा स्वराज, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, वसुंधरा राजे, शीला दीक्षित और स्मृति ईरानी आदि ने सक्रियता दिखाई है।

इंदिरा गांधी ने तो 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया है और तो और इस समय भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु हैं, जो आदिवासी इलाके से आती हैं।

वाम संगठनों में प्रत्याशी के लिए मंथन जारी, एबीवीपी वरिष्ठ छात्र पर लगाएंगी दांव

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव कोविड महामारी के चलते 2019 के बाद से नहीं हुआ है। इस कारण इस बार जेएनयू परिसर में गहमागहमी कुछ ज्यादा ही है। शुक्रवार को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके लिए सभी दलों ने प्रत्याशियों के नाम पर जमकर मंथन किया। जेएनयू में 22 मार्च को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होगा। 24 मार्च को अंतिम परिणाम जारी किए जाएंगे।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्र संघ चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। गुरुवार को छात्र संगठन प्रत्याशियों के नाम पर एकमत होने के लिए मंथन करते रहे। चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सामने सभी वाम संगठन अपने प्रत्याशी उतारते हैं।

एसएफआई और आईसा ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं, लेकिन दूसरे संगठनों से उन नामों पर सहमति बनाई जाने की कोशिश की जा रही है। शनिवार को अंतिम नाम तय होगा। उधर, एबीवीपी वरिष्ठ छात्र पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है।

जेएनयू में 22 मार्च को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होगा। 24 मार्च को अंतिम परिणाम जारी किए जाएंगे। शुक्रवार को 9.30 से शाम पांच बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। शनिवार को शाम तीन बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। उधर, छात्र संगठनों का प्रचार जारी है। हालांकि, उससे पहले सभी प्रत्याशियों के नामों पर एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

कोविड के कारण 2019 से नहीं हुए चुनाव

जेएनयूएसयू में करीब 13 अध्ययन केंद्रों में 48 काउंसलर और चार केंद्रीय पदाधिकारी का चुने जाएंगे। काउंसलर के लिए जेएनयू में सभी छात्र संगठन अपने प्रत्याशी उतारते हैं। लेकिन, चार केंद्रीय पदाधिकारियों के लिए वाम संगठन गठबंधन प्रत्याशी उतारते रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) अकेले चुनाव लड़ती है। कोविड महामारी के चलते 2019 के बाद से चुनाव नहीं हुआ है।

आखिरी बार आईशी घोष बनीं थी अध्यक्ष

आखिरी बार स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की तरफ से अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी उतारा गया था और सभी ने समर्थन दिया था। इसमें आईशी घोष अध्यक्ष चुनीं गईं थीं। उससे पहले 2017-18 में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (आईसा) की तरफ से अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी उतारा गया था। वे अध्यक्ष पद जीते भी थे। इस बार भी आईसा या एसएफआई की ओर से ही अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी उतारा जाएगा। हालांकि एसएफआई 2019 से पहले 2012 में ही अध्यक्ष पद पर लड़ सकी है।

चार साल बाद हो रहे हैं चुनाव

आईसा के पदाधिकारी ने कहा, ₹चार साल से चुनाव नहीं हुए हैं और एसएफआई की अध्यक्ष इस दौरान रहीं हैं। इसलिए एसएफआई से आईसा को समर्थन देने के लिए मनाया जा रहा है।₹ एसएफआई ने विधि और शासन अध्ययन केंद्र के पीएचडी छात्र उमेश यादव को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर, आईसा ने आर्ट्स और एस्थेटिक्स अध्ययन केंद्र के पीएचडी छात्र धनंजय को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। उनकी ओर से मधुरिमा कुंडु का नाम भी आगे चल रहा है।

अध्यक्ष पद के लिए स्वाति सिंह का नाम आगे

डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन (डीएसएफ), ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडेशन (एआईएसफ), बिरसा आंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन (बापसा), छात्र आरजेडी, एनएसयूआई की सहमति के बाद ही इन नामों पर एक राय बन सकेगी। सचिव पद के लिए डीएसफ की अध्यक्ष स्वाति सिंह और सचिव अनघा प्रदीप के नाम आगे हैं। सचिव पद पर बात नहीं बनीं तो इन्हें उपाध्यक्ष या संयुक्त सचिव पद पर उतारा जा सकता है।

NSUI और बापसा एक साथ उतारेंगे उम्मीदवार

एनएसयूआई और बापसा के एक साथ मिलकर लड़ने की भी बात सामने आ रही है। नामांकन के बाद ही तय हो पाएगा कि कौन सा संगठन किस पद पर प्रत्याशी उतारेगा। एबीवीपी पूरी ताकत झोंककर लड़ाई लड़ रही है। जेएनयू इकाई के अध्यक्ष उमेश अजमीरा और वरिष्ठ कार्यकर्ता गोविंद के नाम सबसे आगे हैं।

एमएसपी पर लड़ाई जारी रहेगी... दिल्ली में किसानों की महापंचायत में क्या निकला, आगे की क्या प्लानिंग?

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार को किसानों की महापंचायत आयोजित हुई। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि एमएसपी के लिए लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान महापंचायत के दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की कीले लगाकर दिल्ली आने से रोका। हम उन्हें गांव में आने से रोकेंगे।

नई दिल्ली। रामलीला मैदान में महापंचायत में किसानों ने कहा कि एमएसपी की लड़ाई जारी रहेगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 22 जनवरी 2021 के बाद सरकार ने कोई बात किसानों से नहीं की है। सरकार झूठ बोलती है देश के सामने भी और मीडिया के सामने भी। जब बातचीत ही नहीं करनी तो समाधान क्या करेंगे।

किसी पार्टी से लगाव नहीं- राकेश टिकैत

टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा की रामलीला मैदान में आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में कहा कि देश में सब जगह आंदोलन चल रहे हैं। बहुत से आंदोलन दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि कर्नाटक का आंदोलन होगा और बिहार का आंदोलन होगा तो दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। ये विचारधाओं के आंदोलन है।

जो भी सरकार किसानों के विरुद्ध फैंसलें लेगी उसके विरोध में आंदोलन जारी रहेगा। चाहे वह कोई सी भी सरकार (प्रदेश सरकार) हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो उसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। हमें किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है।

गांव में नहीं घुसने देंगे- दर्शन पाल

किसानों ने महापंचायत में किसान नेताओं ने अपनी एमएसपी, ऋण माफी की मांग को दोहराया। महापंचायत में किसान नेताओं ने साफ किया कि एमएसपी की उनकी लड़ाई जारी रहेगी। महापंचायत के दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर, कीले लगाकर दिल्ली आने से रोका। हम उन्हें गांव में आने से रोकेंगे। गांव में घुसने नहीं देंगे। शासन के विरुद्ध आंदोलन करना होगा।

किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने हरियाणा कृषि विवि की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हर साल एक किसान पर 21376 रुपये का कर्जा चढ़ता है। 2000 से 2015 तक किसानों को एमएसपी से 45 लाख करोड़ रुपये कम मिले अपनी फसलों पर। आज हरियाणा-पंजाब का युवा अपनी जमीन बेचकर विदेश जा रहा है। हम देश को बचने के लिए लड़ रहे हैं।

लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं- किसान

हम अमीर बनने के लिए जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एमएसपी मिलने से हम अरबपति नहीं बन जाएंगे। हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब लड़ते हैं तो हम पर आंसू गैस छोड़ी जाती है, गोलियां चलाई जाती हैं। सरकार खुद मे सुधार नहीं करती तो सरकार को इसका खामियाजा उठाना होगा। अगला जो आंदोलन होगा वह आरपार का होगा।

नर्मदा बचाओं आंदोलन की संस्थापक मेधा पाटेकर ने कहा कि किसानों को न्यूनतम मूल्य भी नहीं देने वाली सरकार, उद्यमियों को अधिकतम मुनाफा करा रही है। किसान को अपनी चीजों का सहीं दाम चाहिए और हर चीज पर चाहिए।

देश की टैक्स पालिसी में सरकार बदलाव करे तो बडे.उद्योगपतियें से मिलने वाले टैक्स से किसानों को आसानी से एमएसपी दिया जा सकता है। देश की टैक्स पालिसी पर संयुक्त किसान मोर्चा भी अपना बयान जारी करे। किसान संगठनों द्वज्ञरा 23 मार्च को देश के सभी गांवा में लोकतंत्र बचाओं दिवस मना कर लखीपुर खिरी में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी को भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया जाएगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है।

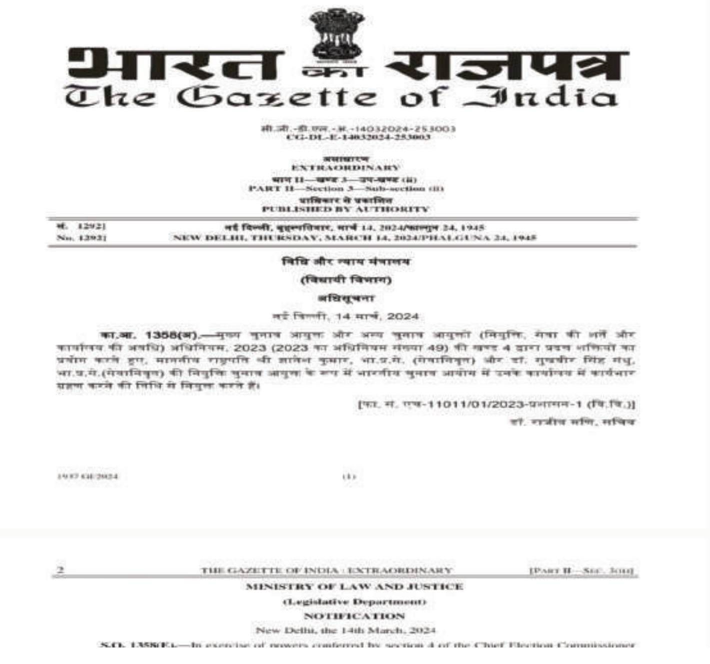
REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-253003
CG-DL-E-14032024-253003

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1292] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945
No. 1292] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

का.आ. 1358(अ).—[illegible]

[फा. सं. एच-11011/01/2023-प्रशासन-1 (वि.वि.)]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi, the 14th March, 2024
S.O. 1358(E).—In exercise of powers conferred by section 4 of the Chief Election Commissioner

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ये हैं अहम बातें

समिति ने सुझाव में कहा है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इसके बाद 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दल तैयारियां कर रहे है। इस सबके बीच लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के सहित विभिन्न निकायों के एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One Nation, One Election) पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है। इसमें कुछ अहम बाते है। आये जानते है।

18,626 पन्नों की है रिपोर्ट

रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान समित ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। इसमें पिछले 191 दिनों के हितधारकों, विशेषज्ञों और अनुसंधान कार्य के साथ व्यापक परामर्श का नतीजा शामिल है।

समिति का ये है सुझाव

समिति ने सुझाव में कहा है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इसके बाद 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। उधर त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में शेष पांच साल की समय अवधि के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं।

पहले चरण में लोकसभा-विधानसभाओं के चुनाव

कोविंद समिति ने कहा कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। वही 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों संबंधी जरूरतों के लिए पहले से योजना बनाने की सिफारिश की। इसके साथ ही चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एकल मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा।

अगले चुनाव में हो सकता है प्रयोग

समिति के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताते है कि समिति 2029 में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव देगी। साथ ही इससे संबंधित प्रक्रियात्मक और तार्किक मुद्दों पर चर्चा करेगी। समिति के ही दूसरे सदस्य ने भी नाम उजागर न करने का अनुरोध करते हुए कहा कि समिति का मानना है कि उसकी सभी सिफारिशें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार पर निर्भर है कि वह उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करे।

बाताया गया है कि रिपोर्ट में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्राची मिश्रा द्वारा एक साथ चुनावों की आर्थिक व्यवहार्यता पर एक पेपर शामिल है। रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों का भी उल्लेख किया जाएगा। आयोग ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक पर विचार किया है। रिपोर्ट में 1951-52 और 1967 के बीच तीन चुनावों के डाटा का इस्तेमाल किया गया है। यहां यह तर्क दिया गया है कि एक पहले की तरह अब भी एक साथ चुनाव करना संभव है। बताया गया कि एक साथ चुनाव कराना तब बंद हो गया था जब कुछ राज्य सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई थीं या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, जिससे नए सिरे से चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी।

6 महीने पहले सौंपा था काम

'एक देश, एक चुनाव' वाली कोविंद समिति देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम पांच अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश कर सकती है। प्रस्तावित रिपोर्ट लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक एकल मतदाता सूची पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। पिछले सितंबर में गठित समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है।

दिल्ली की 3 सीटों पर छूटे कांग्रेस के पसीने! नए समीकरण के बीच इन नामों पर चर्चा

परिवहन विशेष न्यूज

कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक शुक्रवार को प्रस्तावित थी लेकिन इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया। अब सोमवार को होनेवाली बैठक में दिल्ली की तीन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। सीईसी के निर्देशानुसार इसमें हर सीट से एक एक नाम तय कर उसे भेजे जाने हैं। इसी दिन देर शाम तक घोषणा भी कर दी जाएगी।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) से गठबंधन में मिली तीन लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। लगातार बैठकें करने के बावजूद पार्टी इन सीटों से प्रत्याशियों के नाम तय नहीं कर पा रही है। आलम यह है कि संभावित प्रत्याशियों की जोड़तोड़ में नए-नए समीकरण भी जुड़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि राजधानी में सातों लोकसभा सीटों पर आप- कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। चार सीटें आप के पास हैं जबकि तीन कांग्रेस को मिली हैं। दिलचस्प यह कि आप अपने चारों उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब तो भाजपा ने भी अपने सातों प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस तीन उम्मीदवार भी तय नहीं कर पा रही है।

सीईसी की अगली बैठक सोमवार को

प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी चार से पांच बैठकें कर चुकी है। दो बार तो पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की भी बैठकें हो चुकी है। अगली बैठक शुक्रवार को प्रस्तावित थी, लेकिन उसे अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मतलब, कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार सोमवार शाम तक ही घोषित किए जाने के आसार हैं।

पार्टी सूत्र बताते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और पूर्व विधायक भीष्म शर्मा के नाम पर गंभीरता से विचार-विमर्श हो रहा है। वैसे कहने को इस सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी सहित कई अन्य नेता भी ताल ठोक रहे हैं। चांदनी चौक से पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नाम प्राथमिकता से विचाराधीन है।

हरिशंकर गुप्ता भी मजबूत दावेदार

अलका यहां से विधायक भी रह चुकी हैं जबकि जयप्रकाश अग्रवाल का मान सम्मान काफी है। इस सीट से एक अन्य उम्मीदवार पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता भी है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से पूर्व सांसद उदित राज, पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान एवं पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार में से ही किसी एक के नाम पर मोहर लगना तय है।

सूत्र बताते हैं कि भाजपा के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद अब कांग्रेस में हर सीट पर स्थानीय उम्मीदवार को ही टिकट देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने जागरण से बातचीत में कहा कि शुक्रवार को एक बार फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है।

एक-एक नाम भेजे जाएंगे

सीईसी के निर्देशानुसार इसमें हर सीट से एक एक नाम तय कर उसे भेजे जाने हैं। सोमवार को सीईसी की बैठक प्रस्तावित है। संभावना है कि उस दिन तीनों सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर स्वीकृति की मुहर लग जाएगी और उसी दिन देर शाम तक घोषणा भी कर दी जाएगी।

सीखने के लिए दोस्त से ली कार, दिल्ली की मार्केट में कई लोगों को रौंदा; भीड़ देख घबरा गया था नाबालिग

पकड़े गए आरोपित से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि कार चलाना उसकी चाहत थी। एक दोस्त को फोन करके कार का इंतजाम करने को कहा था। जिसके बाद वह एक परिचित कैब चालक से कुछ देर के लिए कार मांगी और नाबालिग को चलाने के लिए दे दिया। वह मयूर विहार फेज-तीन में साप्ताहिक बाजार में भीड़ को देखकर घबरा गया।

पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज-तीन में बुधवार रात कैब से साप्ताहिक बाजार में कई लोगों को रौंदने वाला नाबालिग निकला। कार सीखने के चक्कर में 17 वर्षीय नाबालिग से यह हादसा हुआ। जीवन में तीसरी बार वह कार चला रहा था। उसने नौ लोगों को रौंदा था। हादसे में सीता देवी नाम की युवती की मौत हो गई थी।

एक अन्य नाबालिग फरार

हादासे के वक्त आरोपित के साथ उसका 17 वर्षीय एक दोस्त भी था, जो मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। वही कैब लेकर आया था। घायल तनुजा की शिकायत पर गाजीपुर थाना ने गैरा इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में प्राथमिकी की है। आरोपित को पुलिस ने पकड़ा हुआ है।

पकड़े गए आरोपित से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि कार चलाना उसकी चाहत थी। उसके परिवार में कार नहीं है। परिवार के सदस्य उसे वाहन नहीं चलाने देते थे। उसने बुधवार को पटपड़गंज क्षेत्र में रहने वाले एक दोस्त को फोन करके कार का इंतजाम करने को कहा था। उसके दोस्त ने अपने परिचित कैब चालक से कुछ देर के लिए कार ले ली।

भीड़ देखकर घबरा गया था नाबालिग

वह कार लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा, वहां से वह गाजीपुर चले गए। आरोपित ने अपने दोस्त से कार ले ली और खुद चलाने लगा। उसे कार चलाने का अनुभव नहीं था। वह कार लेकर मयूर विहार फेज-तीन स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के पास पहुंचा, वहां साप्ताहिक बाजार में भीड़ थी। भीड़ को देखकर वह घबरा गया और कार पर नियंत्रण खो बैठा।

वह लोगों को रौंदता हुआ एक ठेले से टकराया, लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो वह डर गया। उसने कार पीछे की और आगे की तरफ बाजार में दौड़ा दी। उसके सामने जो आया वह उन्हें रौंदता हुआ चला गया। करीब तीन सौ मीटर दूर जाकर गिरजाघर के पास भीड़ ने कार समेत चालक को पकड़ लिया था। उसी दौरान आरोपित का दोस्त कार से निकलकर भाग गया था।

अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ढाबे की बिल्डिंग सहित 10 मकानों पर चला बुल्डोजर

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। बृहस्पतिवार को जिले के न्यू कॉलोनी में अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए अभियान चलाया। बुल्डोजर की मदद से अवैध निर्मित हिस्सों को तोड़ा तथा सील करने की भी कार्रवाई की। वहीं हरियाणा के पलवल में एनएचएआई ने बघौला गांव में 37 लोगों के घरों में नोटिस चस्पा किए हैं। जिसमें उनसे हटाने को कहा गया है।

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की एन्फोर्समेंट टीम ने बृहस्पतिवार को न्यू कॉलोनी में अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए अभियान चलाया। दस अवैध निर्माणों को तोड़ने के साथ ही सील भी किया। यह कार्रवाई जोन-एक की एन्फोर्समेंट टीम द्वारा की गई।

अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई

सहायक अभियंता (एन्फोर्समेंट) दीपक कुमार और जेई सचिन कुमार की टीम जेसीबी व पुलिस बल लेकर न्यू कॉलोनी में पहुंची। यहां पर कई निर्माणकर्ताओं ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण किए हुए थे। टीम ने मौके पर बुल्डोजर की मदद से अवैध निर्मित हिस्सों को तोड़ा तथा सील करने की भी कार्रवाई की।

किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ द्वारा चारों जोन की एन्फोर्समेंट टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उनके क्षेत्रों में अतिक्रमण, अवैध निर्माण तथा निगम की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए लगातार कार्रवाई करें।

पलवल में घर हटाने को नोटिस

वहीं, पलवल में एनएचएआई ने बघौला गांव में 37 लोगों के घरों में नोटिस चस्पा किए हैं। चस्पाए गए नोटिस में कहा गया है कि लोग 15 दिनों में अपने अपने घरों को हटा लें। अन्यथा एनएचएआ तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाएगी विभाग की इस कार्रवाई से स्थानीय ग्रामीणों में अपना आशियाना टूटने की चिंता सता रही है। इस तोड़ फोड़ से घबराए ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त नेहा सिंह से मिल कर अपनी व्यथा बताई।

उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए दोबारा से पैमाइश कराए जाने की मांग की है। जिला उपायुक्त ने ग्रामीणों को सही से जांच कराए जाने का भरोसा दिलाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सर्विस लेन के साथ जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने सुरेश चौहान, राजपाल, देवकी, नेतराम, टेकचंद, तेजराज, राम प्रसाद, सोनू, धर्मबीर ने जिला उपायुक्त नेहा सिंह को बताया कि राजमार्ग छह लेन बनाए जाने के बाद बघौला गांव में व्हीकल अंडरपास का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

दो अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने पर छह अभियुक्तों को तीन साल की सजा, एक वर्तमान में ADM के पद पर तैनात

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में सीबीआई कोर्ट ने आईबीपीएस क्लर्क की भर्ती परीक्षा में दो परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने वाले दो अभियुक्तों सहित छह को तीन साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने सभी को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए एक महीने की बेल दे दी है। आरोपितों में एक नवीन तंवर भी शामिल है जो हिमाचल प्रदेश चंबा में एडीएम के पद पर कार्यरत हैं।

गाजियाबाद। नौ साल पहले आयोजित आईबीपीएस क्लर्क की भर्ती परीक्षा में दो परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने वाले दो अभियुक्तों सहित छह को सीबीआई कोर्ट ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरोपितों में एक नवीन तंवर हिमाचल प्रदेश चंबा में एडीएम के पद पर कार्यरत है। वह सजा सुनाये जाने के वक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

13 दिसंबर 2014 को गोविंदपुरम स्थित आइडियल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा थी। सीबीआई को सूचना मिली कि परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरे युवक परीक्षार्थी बनकर परीक्षा दे रहे हैं। सूचना पर सीबीआई की टीम ने मौके पर जाकर अमित सिंह और अजय पाल के स्थान पर परीक्षा दे रहे नवीन तंवर और सावन को पकड़ा। सुग्रीव गुर्जर और हनुमत गुर्जर ने दोनों परीक्षार्थियों को साल्वर मुहैया कराने में बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। इस मामले की अंतिम सुनवाई बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआइ शिवम वर्मा की कोर्ट में हुई।

सजा के खिलाफ अपील के लिए मिली एक महीने की बेल

कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को सावन, अमित सिंह, अजय पाल के साथ हनुमत गुर्जर और सुग्रीव गुर्जर को सजा के खिलाफ अपील के लिए एक महीने की बेल दी है।

मौके पर डीसीपी सिटी ज्ञानंजय सिंह और एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव समेत फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिली है।

गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी, चाकू घोंपकर मां-बेटे को उतारा मौत के घाट; पति की भी हालत

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद जिले में कवि नगर थाना क्षेत्र के महिन्द्रा एन्क्लेव में मां बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक चाकू घोंपकर घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं महिला का पति गंभीर रूप से घायल है। शुरुआती जांच में कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर पत्नी और बेटे की हत्या कर आत्महत्या के प्रयास का मामला पुलिस को लग रहा है।

गाजियाबाद। कवि नगर थाना क्षेत्र के महेंद्रा एन्क्लेव इलाके में बी ब्लॉक के एक घर में मां-बेटे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। महिला का पति लहूलुहान हालत में मिला है। पुलिस ने घायल को सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया है।

महेंद्रा एन्क्लेव बी 1 निवासी अमरदीप शर्मा अपनी पत्नी सोनू और बेटे विनायक वशिष्ठ के साथ रहते हैं। आज दोपहर करीब दो बजे अमरदीप के छोटे भाई ने हिमाचल से अपनी चाची संगीता को फोन कर बताया कि अभी अमरदीप का फोन आया है। उसने बताया कि किसी ने उनपर हमला कर दिया है। उन्हें बचा लो। संगीता जब घर पर आई तो गेट नहीं खुला। उन्होंने पड़ोसन की मदद से दरवाजा खोला। अंदर कमरे में खून देखकर महिलाएं घर से बाहर की तरफ भागी और शोर मचा दिया।

कर्ज न चुकाने के कारण घटना को दिया अंजाम

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को महिला सोनू शर्मा और बेटे विनायक का शव बेड पर मिला। जबकि अमरदीप लहूलुहान हालत में मिले। अमरदीप पलंग के पास नीचे मिला। शुरुआती जांच में कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर पत्नी और बेटे की हत्या कर आत्महत्या के प्रयास का मामला पुलिस को लग रहा है।

हिमाचल का रहनेवाला है परिवार

मौके पर डीसीपी सिटी ज्ञानंजय सिंह और एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव समेत फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिली है। डीसीपी सिटी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या कर आत्महत्या का लग रहा है। सुसाइड नोट में यह बात लिखी गई है। पड़ोसियों का कहना है कि अमरदीप मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले हैं। कांगड़ा में उनका क्राकरी का काम भी है।

पार्षद उर्मिला चौहान का लंबी बीमारी के कारण निधन, संयुक्त मोर्चा ने धरना किया स्थगित

गाजियाबाद नगर निगम में वार्ड संख्या 19 की पार्षद उर्मिला चौहान का गुरुवार को निधन हो गया। इसकी सूचना मिलते ही नगर निगम सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने तीन दिन से चल रहा धरना स्थगित कर दिया है। निगम के सफाई कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरी करने की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर शुक्रवार से कूड़ा उठान बंद करने की चेतावनी दी थी।

गाजियाबाद। नगर निगम में वार्ड संख्या 19 की पार्षद उर्मिला चौहान का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थीं, उनका उपचार दिल्ली स्थित एम्स में किया जा रहा था। पार्षद की मौत की सूचना के बाद नगर निगम सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने तीन दिन से चल रहा धरना स्थगित कर दिया है। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी धरने के माध्यम से नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरी करने की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर शहर में कूड़ा उठान का कार्य शुक्रवार से बंद करने की चेतावनी दी गयी थी। उधर, नगर निगम कार्यालय में शाम चार बजे शोकसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, महापौर, पार्षद द्वारा पार्षद उर्मिला चौहान की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया जाएगा।

नोएडा के छात्रों के लिए खुशखबरी, 20 मार्च तक इनके खाते में आ जाएंगे पांच हजार रुपये

नोएडा के निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीट पर सत्र 2023-24 में दाखिला पाने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को पांच हजार रुपये की राशि दी जाएगी। बीते कई सालों से इन्हें यह राशि नहीं मिल रही थी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से की गई पहल के कारण 2566 छात्रों के खातों में 20 मार्च तक अब पांच पांच हजार रुपये की राशि पहुंच जाएगी।

ग्रेटर नोएडा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीट पर सत्र 2023-24 में दाखिला पाने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के साथ अब किताब, कॉपी और बैग खरीदने के लिए एक करोड़ 28 लाख 30 हजार रुपये का बजट जारी किया गया है। स्कूलों को छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति करने के लिए पिछले सत्र में बजट दिया गया था, लेकिन छात्रों को मिलने वाले पांच-पांच हजार रुपये कई सालों से नहीं मिल पाए थे, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से की गई पहल के कारण 2566 छात्रों के खातों में 20 मार्च तक अब पांच पांच हजार रुपये की राशि पहुंच जाएगी।

पांच हजार रुपये मिलने से काफी मदद मिलेगी : अभिभावक राकेश ने बताया कि पांच हजार रुपये मिलने से काफी मदद मिलेगी। नए सत्र में उन्हें उधार लेकर बच्चों की कॉपी, किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। वहीं राखी ने बताया कि उनका बच्चा तीन साल से आरटीई के तहत पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पहली बार पांच हजार रुपये मिलने से राहत मिलेगी।

224 स्कूलों को होगी छह करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति : छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति होने से स्कूल प्रबंधन भी खुश दिखाई दे रहे है। 224 स्कूलों के लिए छह करोड़ 71 लाख रुपये जारी हुए है। प्रत्येक छात्र के हिसाब से 450 रुपये हर माह शासन की ओर से स्कूलों को दिए जाते है। 20 मार्च तक स्कूलों के खातों में भी आरटीई के तहत पढ़ाई कर रहे छात्रों की फीस पहुंच जाएगी।

इंडिया गठबन्धन की उलझनों से चुनावों में भाजपा की राह आसान होती दिख रही है

ललित गर्ग

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक होंगे। ऐसी संभावनाएं हैं कि भाजपा शारदार एवं ऐतिहासिक जीत को सुनिश्चित करने के लक्ष्य को लेकर सक्रिय है। नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि इन चुनावों के परिणाम उनके 400 सीटों के लक्ष्य को हासिल करें।

इंडिया गठबन्धन लगातार कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-एनडीए में नये दलों के जुड़ने की खबरों से उसके बड़े लक्ष्य के साथ जीत की राह आसान होती जा रही है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निश्चित किया है। भाजपा जहां इस बडे.लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पुराने सहयोगियों को फिर से साध रही है तो दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में करने पर भी पार्टी का जोर है और वह इसमें बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर रही है। ओडिशा में बीजेडी और आंध्र में टीडीपी से गठबंधन पक्का माना जा रहा है। त्रिपुरा का मुख्य विपक्षी दल टिपरा मोथा भी अब भाजपा सरकार में शामिल हो गया है। भाजपा पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक चुनावी समीकरण सेट करने एवं विभिन्न दलों को एनडीए में शामिल करने की रणनीति में जुटी है। भाजपा ने अभी अनेक प्रांतों में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, ताकि दूसरे दलों के एनडीए में शामिल करने एवं उनसे सीटों के समीकरण को सेट करने के दरवाजे खुले रहे। निश्चित रूप से भाजपा की यह मजबूत होती स्थिति विपक्ष की एकता के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती क्योंकि इंडिया गठबन्धन विभिन्न मजबूत क्षेत्रीय दलों का ही गठबन्धन माना जाता है जिसमें कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। समाजवादी पार्टी एवं आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों में उतना दम नहीं है, या अनेक मजबूत दल एनडीए के साथ जुड़ चुके हैं या उन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ने की घोषणा करके इंडिया गठबन्धन की सांसें छीन ली है। इन नये गठजोड़ों से बनते राजनीतिक परिदृश्य इंडिया गठबन्धन के लिये चिन्ता का कारण है।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक होंगे। ऐसी संभावनाएं हैं कि भाजपा शारदार एवं ऐतिहासिक जीत को सुनिश्चित करने के लक्ष्य को लेकर सक्रिय है। नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि इन चुनावों के परिणाम उनके 400 सीटों के लक्ष्य को हासिल करें। इसलिये भाजपा विभिन्न दलों को एनडीए में शामिल करने के जोड़-तोड़ में लगी है। इस चुनाव को लेकर चुनावी गठबंधनों का दौर चल रहा है। राजनीतिक दल चुनावी गठबंधनों और सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में क्षेत्रीय दलों को जोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ खड़ा है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने भी कुछ राज्यों में अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बात बना ली है। कुछ पर अब भी बात चल रही है। भाजपा ने 2 मार्च को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम थे। कुछ ऐसे राज्य बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक हैं जहां से भाजपा ने एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। इन राज्यों के एक भी सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं करने का कारण है- भाजपा की अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन या गठबंधन के दलों के साथ सीट शेयरिंग पर अब भी चल रही बातचीत में संभावनाएं तलाशने की रणनीति।

लोकसभा चुनाव सन्निकट हैं। इंडिया गठबन्धन एवं एनडीए रूठे नेताओं को मनाने, गठबंधन का गणित सेट करने और पुराने सहयोगियों को फिर से साथ लाकर कुनबा बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हैं। भाजपा ने इन चुनावों में 'अबकी पार, 400 पार' का नारा दिया है। अब पार्टी इस नारे को चुनाव नतीजे में तब्दील करने के लिए व्यापक स्तर पर गठबंधनों की संभावनाओं को तलाश रही है। ओडिशा में बीजू जनता दल और भाजपा का गठबंधन पक्का माना जा रहा है। अगर ये गठबंधन होता है तो राज्य में दोनों ही दलों को बढ़िया चुनाव परिणाम मिल सकते हैं। कारण कि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस को मात्र 1 सीट पर जीत मिली थी और वर्तमान में यहां की राजनीति पर नवीन पटनायक की मजबूत पकड़ बताई जाती है। लोकसभा

और विधानसभा के चुनावों में दोनों पार्टियां 11 सालों तक गठबंधन में रहीं। इस दौरान दोनों दलों का राज्य की राजनीति पर दबदबा बना रहा। पटनायक राजनीति के महारथी हैं, उनको भाजपा के साथ गठबंधन करना ही पार्टी एवं राज्य की जनता के हित में प्रतीत हो रहा है।

बीजू जनता दल की पिछले 25 वर्षों से ओडिशा में सरकार है और इसके मुख्यमन्त्री नवीन पटनायक इस पार्टी के एकछत्र नेता माने जाते हैं और इस दल का 2009 तक भाजपा से सहयोग था और यह एनडीए का हिस्सा था। 1998 में जब एनडीए का गठन हुआ था तो बीजू जनता दल स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इसमें शामिल हुआ था। मगर 2008 में ओडिशा के कन्धमाल में भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए थे जिनमें भाजपा पर भी गंभीर आरोप लगे थे। उसके बाद 2009 में बीजू जनता दल लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से बाहर आ गया था। अब पुनः 15 वर्ष बाद वर्ष 2024 के आम चुनाव में ही यह पुनः एनडीए में शामिल हो रहा है और मोदी के नेतृत्व में राज्य को विकास की नयी ऊंचाइयां देना चाहते हैं। नवीन बाबू की वरीयता राज्य शासन पर काबिज रहना है और भाजपा का लक्ष्य केन्द्र की सरकार पर आरुढ़ रहना है। दोनों पार्टियां एक-दूसरे के लक्ष्य को पूरा करने में एक-दूसरे की सहायक हो सकती हैं।

अतः इससे विपक्ष का यह विमर्श भी निस्तेज पड़ता है कि श्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से देश में भाजपा विरोध का समां बंधा है। मोदी के प्रभावी नेतृत्व का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रीय दल भाजपा का समर्थन करते हुए न केवल अपनी राजनीति को जीवंत रखना चाहते हैं बल्कि नया भारत-सशक्त भारत बनाने में खुद को शामिल करना चाहते हैं।

ओडिशा की ही तर्ज पर बिहार में भी नीतीश को मोदी के नेतृत्व में हित दिखाई दिया है। यही कारण है लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में राजनीतिक बदलाव करते हुए नीतीश एनडीए से जुड़ गये। इस बदलाव से राज्य में भाजपा और नीतीश कुमार को इस चुनाव में बड़ा फायदा होने की संभावनाएं है। राज्य में भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के अलावा इन दलों का भी साथ है- चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (लोजपा रामविलास), चिराग के चाचा पशुपति पारस की लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। लेकिन इन दलों एवं भाजपा के बीच कई कारणों से पेंच फंसे हुए है, सीटों के बंटवारे को लेकर समझौते के तार उलझे हुए हैं, जो निकट भविष्य में सुलझ जाने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र की 48 सीटों में से करीब 32 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ सकती है, वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लगभग 12 सीट और अजित पवार की एनसीपी को लगभग 4 सीटें मिल सकती हैं। राज्य में 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में भाजपा के साथ शिव सेना ने चुनाव लड़ा था। भाजपा ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 23 पर जीत हासिल की थी। वहीं शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और 18 पर जीत दर्ज की। तब कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में साथ थे। एनसीपी को 4 सीटों पर और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। उधर आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी का गठबंधन हो सकता है। 7 मार्च को टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद गठबंधन की अटकलों को बल मिल गया है। राज्य में भाजपा, टीडीपी और जन सेना के बीच गठबंधन को लेकर बातें तय हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, टीडीपी भाजपा के लिए 6 सीटें छोड़ने पर सहमत हो गई है। विभिन्न गैर भाजपा राज्यों में भाजपा की स्थिति अनुकूल बनती जा रही है, जिससे उसका 400 सीटों के पार का लक्ष्य हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबन्धन की उलझनों में उलझी हुई है। ये उलझने ही भाजपा की राह को आसान बना रही हैं।

Citroen के फैंस के लिए कंपनी उठाने जा रही यह कदम, सर्विस नेटवर्क के साथ बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस

परिवहन विशेष न्यूज

Citroen ने गुरुवार को कहा कि उसकी चालू कैलेंडर वर्ष के अंत तक पूरे भारत में 200 से अधिक सेल्स और सर्विस टचप्वाइंट खोलने की योजना है। आपको बता दें कि सिट्रोएन और जीप स्टेलेंटिस मदरशिप का हिस्सा हैं। इसकी ओर से देश के सेमी-अर्बन और रूरल मार्केट में प्रवेश करने पर विचार किया जा रहा है। कंपनी स्मार्ट रिटेल विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है।

नई दिल्ली। Citroen ने गुरुवार को कहा कि उसकी चालू कैलेंडर वर्ष के अंत तक पूरे भारत में 200 से अधिक सेल्स और सर्विस टचप्वाइंट खोलने की योजना है। यह स्वीकार करते हुए कि इसके लिए कुछ गंभीर प्रयास करने होंगे, क्योंकि वर्तमान में यहां उसके 58 टचप्वाइंट हैं। आइए, पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

Citroen का सफर

Citroen अपने पहले मॉडल C5 Aircross के साथ सितंबर 2022 में मैदान में प्रवेश करने के साथ भारत में कार निर्माताओं की नई पीढ़ी में से एक है। इस प्रीमियम कार के बाद कंपनी ने C3, E-C3 (इलेक्ट्रिक कार) और C3 Aircross जैसे अधिक किफायती विकल्पों के साथ इंडियन मार्केट में अपना विस्तार किया।

कंपनी का फ्यूचर प्लान

सिट्रोएन का मानना है कि उसके नेटवर्क में 400 प्रतिशत की वृद्धि उसे मजबूत स्थिति में लाएगी। कंपनी द्वारा जारी एक प्रेस बयान में सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड निदेशक शिशिर मिश्रा ने कहा-

हम आक्रामक रूप से सिट्रोएन को उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं और अपने उत्पादों की क्षमता को टियर I/टियर II शहरों से आगे बढ़ाना चाहते हैं। टियर III और यहां तक कि टियर IV बाजारों के लिए, रणनीतिक रूप से टियर I और टियर II शहरों से निकटता और पर्याप्त विकास की उनकी क्षमता के लिए चुना गया है।

आपको बता दें कि सिट्रोएन और जीप स्टेलेंटिस मदरशिप का हिस्सा हैं। citroen की ओर से देश के सेमी-अर्बन और रूरल मार्केट में प्रवेश करने पर विचार किया जा रहा है। कंपनी स्मार्ट रिटेल विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है।

अब AI से होगी सड़कों की मरम्मत! मिनटों में गड्ढे का पता लगाकर ठीक कर देता है ये रोबोट

यूके से एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहां एक लोकल काउंटी ने अपनी गड्ढों से भरी सड़कों की मरम्मत के लिए एआई तकनीक का उपयोग किया है। यूके में हर्टफोर्डशायर काउंटी काउंसिल ने अपने अधिकार क्षेत्र में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए रोबोटिज3डी टेक कंपनी से एक नया रोबोट पेश किया है।

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तेजी से हमारे जीवन का एक मजबूत हिस्सा बनता जा रहा है। AI ने हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर सिस्टम से लेकर जटिल एल्गोरिदम चलाने तक की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया है।

रोबोट बना रहा सड़कें

यूके से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहां एक लोकल काउंटी ने अपनी गड्ढों से भरी सड़कों की मरम्मत के लिए एआई तकनीक का उपयोग किया है। यूके में हर्टफोर्डशायर काउंटी काउंसिल ने अपने अधिकार क्षेत्र में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए रोबोटिज3डी टेक कंपनी से एक नया रोबोट पेश किया है।

लिवरपूल यूनिवर्सिट ने किया है डेवलप

इस रोबोट को ARRES (ऑटोनॉमस रोड रिपेयर सिस्टम) नाम दिया गया है और इसे रोबोटिज़3डी के साथ मिलकर लिवरपूल यूनिवर्सिट द्वारा डेवलप किया गया है। ARRES रोबोट AI की मदद से सड़क पर गड्ढे और अन्य दिक्कतों का पता लगाकर उन्हे सही कर देता है।

क्या भारत में भी ऐसा समाधान ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 2023 में नागपुर में सड़क सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग (iRASTE) AI-पावर्ड प्रोजेक्ट के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बेहतरीन समाधान भी लागू किया है। इस परियोजना का लक्ष्य सड़क सुरक्षा में 50 प्रतिशत तक की गिरावट हासिल करना है। हालांकि, जब AI का उपयोग करके गड्ढों को ठीक करने की बात आती है तो ARRES रोबोट पहला और एकमात्र समाधान है। उम्मीद है कि भारत इस तकनीक को अपनाने और गड्ढों की पहचान करने के अलावा एक बेहतर तकनीक बनाने की कोशिश करेगा।

मारुति की दो हैचबैक और एक SUV को मिलेगा अपडेट हाइब्रिड तकनीक के साथ मिलेगा 35 से ज्यादा का एवरेज

देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता मारुति सुजुकी की ओर से जल्द ही अपनी दो Hatchback और एक SUV को अपडेट किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इनमें Hybrid तकनीक को दिया जा सकता है। जिससे इनके एवरेज में बढ़ोतरी हो जाएगी। कंपनी की ओर से कब तक और किन गाड़ियों में यह तकनीक दी जा सकती है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी तीन गाड़ियों को अपडेट कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से इन तीनों गाड़ियों में नई तकनीक को दिया जा सकता है। जिसके बाद इनका एवरेज 35 किलोमीटर प्रति लीटर तक हो सकता है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि कंपनी की ओर से किन गाड़ियों को हाइब्रिड तकनीक के साथ कब तक लाया जा सकता है।

मिलेगी नई तकनीक

मारुति सुजुकी लगातार अपने पोर्टफोलियो को अपडेट कर रही है। कंपनी की ओर से जल्द ही हाइब्रिड तकनीक के साथ तीन गाड़ियों को लाया जा सकता है। मौजूदा समय में कंपनी माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक के साथ कई गाड़ियों को ऑफर करती है। जिनमें सियाज, अर्टिगा से लेकर इनविक्टो और ग्रैंड विटारा तक शामिल हैं। लेकिन अब कंपनी इन हाऊस एचईवी सिस्टम को डेवलप करने पर काम कर रही है।

किन गाड़ियों में मिलेगी तकनीक

कंपनी की ओर से अभी इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जिन गाड़ियों को इस तकनीक के साथ लाया जा सकता है, उनमें फ्रॉन्क्स, बलेनो और स्विफ्ट शामिल हैं। इन तीनों गाड़ियों में इस नई तकनीक को देने के बाद ही अन्य कारों में भी इसे दिया जाएगा। एचईवी सिस्टम को फ्रॉन्क्स में अगले साल तक लाया जा सकता है। इसके बाद 2026 तक बलेनो को भी अपडेट दिया जा सकता है।

क्या होगा फायदा

एचईवी सिस्टम के साथ ही पेट्रोल इंजन वाली कारों को ज्यादा दूरी तक चलाया जा सकेगा। इन कारों में कंपनी 1.2 लीटर का जेड सीरीज तीन सिलेंडर इंजन देगी। नई तकनीक के साथ इन कारों का एवरेज बढ़कर 35 किलोमीटर प्रति लीटर तक हो सकेगा। ऐसा होने के बाद कंपनी की ये गाड़ियां अपने अपने सेगमेंट में अन्य कंपनियों के उत्पादों को कड़ी चुनौती दे पाएंगी।

Skoda ने लॉन्च से पहले दिखाया अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार का इंटीरियर, जानिए कितनी खास है Elroq EV

परिवहन विशेष न्यूज

Skoda Auto ग्लोबल मार्केट में किफायती Electric Car पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उम्मीद है कि स्कोडा एलरोक एक इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी जो आकार में कॉम्पैक्ट है। ये इलेक्ट्रिक कार निर्माता का नया एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक वाहन होगा जो EV सेगमेंट में Enyaq भी पेश करता है। आइए इसको लेकर पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Skoda Auto ग्लोबल मार्केट में किफायती Electric Car पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। Elroq नाम की ये आगामी इलेक्ट्रिक कार चेक ऑटो दिग्गज की सबसे छोटी और साथ ही ईवी सेगमेंट में सबसे किफायती मॉडल होगी। कार निर्माता ने इस ईवी की पहली झलक साझा की है। कंपनी ने अपने Elroq EV का इंटीरियर स्केच शेयर किया है।

Skoda Elroq में क्या खास?

उम्मीद है कि स्कोडा एलरोक एक इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, जो आकार में कॉम्पैक्ट है। ये इलेक्ट्रिक कार निर्माता का नया एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक वाहन होगा, जो EV सेगमेंट में Enyaq भी पेश करता है।

लॉन्च टाइमलाइन

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को अगले साल की शुरुआत में वैश्विक बाजारों में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। भारत में बड़े पैमाने पर ईवी सेगमेंट में प्रवेश करने में स्कोडा की रुचि को देखते हुए, इसे बाद की तारीख में यहां भी लॉन्च करने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इंटीरियर और डिजाइन

इंटीरियर के स्केच में देखा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक कार थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और पीछे एक छोटी डिजिटल स्क्रीन के साथ आएगी। डैशबोर्ड पर एक बड़ा और फ्लोटिंग टचस्क्रीन डिस्प्ले है। इसके नीचे आठ बटनों की एक रो है, जो देखने में फिजिकल नजर आती है। केबिन में डैशबोर्ड और दरवाजों पर एलईडी एम्बिएंट लाइटिंग भी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्कोडा एलरोक इलेक्ट्रिक एसयूवी कार निर्माता की लोकप्रिय एसयूवी कारॉक पर आधारित होने की संभावना है। कुछ डिजाइन एलीमेंट के दो साल पहले प्रदर्शित स्कोडा विजन 7एस कॉन्सेप्ट से प्रेरित होने की भी उम्मीद है। इस ईवी की लंबाई करीब चार मीटर होने की संभावना है।

एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार होने के नाते, स्कोडा एलरोक को Enyaq में इस्तेमाल किए गए बैटरी पैक की तुलना में छोटे बैटरी पैक से लैस होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Elroq में 50kWh से 75kWh क्षमता के बीच बैटरी पैक के दो विकल्प हो सकते हैं।

Audi Q6 e-tron 18 मार्च को करेगी ग्लोबल एंट्री, भारत में लॉन्चिंग को लेकर है ये अपडेट

परिवहन विशेष न्यूज

Q6 e-tron का मुख्य आकर्षण इसका इंटीरियर है जिसमें रोटेबल और पैनोरमिक 14 .5-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और 11 .9-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसके अलवा पैसेंजर को पर्सनलाइज्ड फैसिलिटी के लिए डैशबोर्ड में इंटीग्रेटेड 10 .9-इंच स्क्रीन भी मिलती है। Q6 e-tron अपने 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर की बदौलत 600 किमी की अधिकतम रेंज और 270kW तक की फास्ट चार्जिंग रेट का दावा करती है।

नई दिल्ली। Audi ने अपनी Q6 e-tron के कई टीजर जारी करने के बाद ग्लोबल डेब्यू की तारीख भी बता दी है। कंपनी ने कहा है कि Audi Q6 e-tron 18 मार्च को वैश्विक रुप से पेश की जाएगी। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

Audi Q6 e-tron में क्या खास?

Q6 e-tron का मुख्य आकर्षण इसका इंटीरियर है, जिसमें रोटेबल और पैनोरमिक 14.5-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और 11.9-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसके अलवा पैसेंजर को पर्सनलाइज्ड फैसिलिटी के लिए डैशबोर्ड में इंटीग्रेटेड 10.9-इंच स्क्रीन भी मिलती है।

स्पेस की नहीं होगी कमी

कार में 526 लीटर का बूट स्पेस है, जिसे पीछे की सीटों को मोड़कर 1529 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं, इसमें 64 लीटर का फ्रंक भी दिया गया है। पोर्शे के सहयोग से पीपीई इलेक्ट्रिक कार प्लेटफॉर्म पर विकसित, क्यू6 ई-ट्रॉन अपना बेस पोर्शे मैकन ईवी के साथ साझा करेगी।

बैटरी, मोटर और रेंज

Q6 e-tron अपने 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर की बदौलत 600 किमी की अधिकतम रेंज और 270kW तक की फास्ट चार्जिंग रेट का दावा करती है। प्रदर्शन के आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन ऑडी ने संकेत दिया है कि Q6 ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक अपने ट्विन-मोटर की बदौलत 470hp का संयुक्त आउटपुट और 800Nm का पीक टॉर्क पेश करेगी।

भारत में कब होगी लॉन्च?

Audi Q6 e-tron 18 मार्च को ग्लोबली अनवील की जाती है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि Q5 का इलेक्ट्रिक विकल्प जल्द ही भारत में एंट्री करेगा। वर्तमान में ऑडी के पास भारतीय बाजार में कई ईवी हैं, जिनमें Q8 e-tron, Q8 e-tron Sportback, e-tron, e-tron Sportback, e-tron GT और RS e-tron GT शामिल है।

सीएए का विरोध करने वाले लोग मानवता के विरोधी प्रतीत हो रहे हैं

डॉ. आशीष वशिष्ठ

बीते दिनों नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए देश में लागू हो गया है। इस कानून की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद से पास किया था। जनवरी 2020 में राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ यह कानून अस्तित्व में आ गया था। सीएए को लेकर देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुआ था। केंद्र सरकार ने देशभर में एनआरसी लागू करने की बात कही थी। एनआरसी के तहत भारत के नागरिकों का वैध दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्रेशन होना था। सीएए के साथ एनआरसी को मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने के रूप में देखा गया था।

इस कानून को लागू किए जाने को लेकर एक तरफ खुशी का माहौल है तो दूसरी ओर विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। खुशी उन लोगों को है जो बरसों से भारत की नागरिकता पाने का इंतजार कर रहे थे। इस कानून के लागू होने के बाद उनकी दशकों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। विरोध करने वाली जमात में मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल और स्वयंसेवी संगठन हैं। राजनीतिक दल व संगठन इसे पूर्व की भांति तरह अल्पसंख्यक विरोधी बता रहे हैं, वहीं इसे राजनीतिक दांव भी बता रहे हैं।

सीएए लागू होने के बाद विपक्षी दल इस कानून को लेकर देशवासियों को खासकर मुस्लिम समुदाय को भ्रमित कर रहे हैं। असल में, आजादी के बाद से ही अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों की समूची मानसिकता राजनीतिक दलों और उनके संरक्षक बनने का दावा करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के ही समझ के अनुसार चलती रही है। सीएए के खिलाफ उठे देशव्यापी विवाद को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। विपक्ष अपने बयानों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को यह संदेश दे रहा है कि इस कानून से उनकी नागरिकता संकट में पड़ जाएगी। सरकार और जिम्मेदार पदों पर आसीन लोग इस कानून से जुड़ी तमाम आशंकाओं को दूर कर रहे हैं। लेकिन, विपक्ष मुस्लिम समुदाय को गलत जानकारी देकर उपद्रव और हिंसक प्रदर्शनों के लिए परोक्ष रूप से उकसाता दिखाई दे रहा है। 2020 में विपक्ष ने परोक्ष रूप से कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों और उपद्रव में सहायता की थी। ये खुला तथ्य है।

नागरिकता संशोधन नियम लागू होने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता बिना वैध पासपोर्ट और भारत के वीजा के बिना मिल सकती है। दरअसल, ये लोग उन देशों में अल्पसंख्यक हैं। जाने किस त्रास या संकट में उन्हें उन देशों को छोड़ कर आना पड़ा। यहां के नागरिक न होते हुए भी दिक्कतों, मुसीबतों को गले लगाकर यहां जीवन बिताना पड़ रहा है। इसलिए इन सबको नागरिकता देकर यहां यानी भारत में सम्मान दिए जाने के इरादे से यह कानून लाया गया है। ऐसे में अब प्रश्न उठता है कि यह कानून भलाई के रूप में सामने लाया जा रहा है तो विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है?

> यह कानून किसी की नागरिकता का हनन नहीं कर रहा बल्कि वंचितों को कानूनन अधिकार दे रहा है। यह अधिनियम किसी को बुलाकर भी नागरिकता नहीं दे रहा बल्कि जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया वे ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे।

विपक्ष का कहना है कि इस कानून में खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो समानता के अधिकार की बात करता है। इस कानून में इन तीन देशों से आए मुसलमानों को नागरिकता देने से बाहर रखा गया है। कई आलोचकों का मानना है कि इस कानून से मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है और ये भारत में समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। जहां तक विपक्ष के विरोध का सवाल है उसका कहना है कि इस कानून में मुस्लिमों को वंचित क्यों रखा गया? यह समानता के कानून का उपहास उड़ाने की तरह है।

सरकार का कहना है कि जिन देशों के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया जा रहा है, वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि बहुसंख्यक हैं। इसलिए उन्हें इस देश में यानी भारत में नागरिकता देने का कोई मतलब नहीं है। वो उनके देश हैं, वे वहां खुशी से रहें। भारत सरकार वंचितों की मदद करना चाहती है, इसलिए इन तीनों देशों के वे गैर मुस्लिम नागरिक जो वर्षों पहले यहां आ गए थे उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। इसमें गलत क्या है? लेकिन अब विपक्ष के इस विरोध की सच्चाई और इसके पीछे छिपी कुत्सित इरादे देशवासियों को समझ आने लगे हैं।

यह कानून किसी की नागरिकता का हनन नहीं कर रहा बल्कि वंचितों को कानूनन अधिकार दे रहा है। यह अधिनियम किसी को बुलाकर भी नागरिकता नहीं दे रहा बल्कि जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया वे ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े मंत्री और जिम्मेदार लोग इस बात को कई बार कह चुके हैं कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं।

असल में, मोदी सरकार के दस सालों के कार्यकाल में देष में बड़े परिवर्तन और काम हुए हैं। देश की जनता का भरोसा मोदी की गारंटी पर है। दस साल के कार्यकाल के बाद भी पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। मोदी सरकार की लोकप्रियता और देशवासियों के उसके प्रति विश्वास से विपक्ष में बेचैनी का माहौल है। ऐसे में कुंठित और मुद्दा विहीन विपक्ष जात पात की राजनीति और मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा किसी मुद्दे की तलाश में रहता है।

चार साल पहले सीएए कानून बनने के बाद पर्दे के पीछे रहकर विपक्ष दलों ने मुस्लिम समुदाय को भ्रमित कर भड़काया था। नतीजतन देष में अशांति और भय का माहौल बना। हिंसक प्रदर्शनों में जान माल का नुकसान हुआ। आज भी विपक्ष चार साल पहले वाला माहौल बनाना चाहता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार-बार कह रही हैं कि वे पश्चिम बंगाल में सीएए को लागू नहीं होने देंगी। हालांकि संसद के पारित कानून को लागू न करने देना अवैधानिक ही माना जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल सीएए के मुद्दे पर लगातार विभाजनकारी बयानबाजी कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस, सपा, राजद, वाम दल तथा मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के पेट में मरोड़ उठ रहा है।

देश में शरणार्थियों की संख्या की बात करें एक रिपोर्ट के अनुसार 199,931 हैं। यह आंकड़ा 2014 तक का है। 2022 की बात करें तो देश में 242,835.00 शरणार्थी हैं। लेकिन जो 2014 तक भारत आए थे सिर्फ उन्हें ही नागरिकता देने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिसंबर 2021 में राज्यसभा में बताया था कि वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2021 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुल 3,117 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी गई। हालांकि आवेदन 8,244 मिले थे। वहीं गृह मंत्रालय की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2021 में कुल 1,414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई।

पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक जान बचाकर भारत आने में सफल रहे थे वे यहां की नागरिकता पाने का इंतजार बरसों से कर रहे हैं। उनकी संख्या अच्छी-खासी है। वे अल्पसंख्यक होने के कारण ही इन तीनों देशों में प्रताड़ित किए गए। उनके पास प्रताड़ना से

संपादक की कलम से

हरियाणा के नए 'नायब'

पार्टी आलाकमान का ऐसा एकाधिकार भी किसी लोकतंत्र का हिस्सा होता है, हमें याद नहीं है, लेकिन देश की सबसे बड़ी और सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा और एकाधिकार से ही संचालित होती है। प्रधानमंत्री की अचानक इच्छा हुई, तो हरियाणा के उस मुख्यमंत्री को, कुछ ही घंटों में, बदल दिया गया, जिसे जनादेश हासिल था। यह जनादेश अक्तूबर, 2024 के अंत तक का था। 2019 का विधानसभा चुनाव जिसके नेतृत्व में लड़ा गया और 41 विधायक जीत कर आए। यही नहीं, जो शख्स प्रधानमंत्री का 40 साल पुराना दोस्त रहा हो और एक दिन पहले ही सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री ने उनके अभूतपूर्व विकास-कार्यों की प्रशंसा की हो! मोटर साइकिल पर बिताए उन दिनों को याद किया हो, जब वे संगठन के लिए सक्रिय थे! सिर्फ रात ही बीती थी, क्योंकि सुबह तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पद से इस्तीफा देना था! अंतरंग दोस्ती एकदम सूख गई और एक राज्य का मुख्यमंत्री 'पराजित योद्धा' मान लिया गया। मुख्यमंत्री का नया दायित्व लोकसभा सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को सौंप दिया गया। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेतृत्व को 'फीडबैक' मिला होगा कि मुख्यमंत्री खट्टर के कारण जातीय समीकरण बिगड़ रहे हैं। जनता का एक बड़ा हिस्सा उनसे नाराज हो सकता है। चूंकि वह 2014 से ही निरंतर मुख्यमंत्री बने रहे हैं, लिहाजा सत्ता-विरोधी लहर भी स्वाभाविक है।

चुनाव से ऐन पहले ही मुख्यमंत्री बदलने का औचित्य मोदी ही बता सकते हैं, यदि उनकी इच्छा हो! प्रधानमंत्री की बुनियादी चिंता लोकसभा चुनाव है। यदि हरियाणा में जनादेश आधा-अधूरा रहा, तो 370 लोकसभा सीट का लक्ष्य पूरा कैसे होगा? क्या हरियाणा के नए 'नायब' प्रधानमंत्री के लक्ष्य को 100 फीसदी परवान चढ़ा सकेंगे? आपको कुछ ऐतिहासिक याद दिला दें कि जब नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी थे, तो खट्टर सह-प्रभारी होते थे। उस दौर में भाजपा के 4-5 विधायक ही जीत पाते थे। देवीलाल सरीखे नेताओं के साथ गठबंधन होते रहते, तो 17-18 विधायक जीत पाते थे और सरकार में भी भागीदारी हो पाती थी। अटल-आडवाणी की भाजपा तक यही ताकत हुआ करती थी। दरअसल हरियाणा का जातीय समीकरण कभी भी भाजपा-समर्थक नहीं रहा। जाट आबादी का वर्चस्व ऐसा रहा कि 33 सालों तक जाट मुख्यमंत्री ने ही शासन किया। इस बार संकट यह महसूस किया गया कि यदि देवीलाल के प्रपौत्र दुष्यंत चौटाला की जजपा के साथ गठबंधन बरकरार रहता, तो करीब 22 फीसदी जाट वोट कांग्रेस की ओर धुरवीकृत हो सकते थे, लिहाजा सबसे पहले जजपा के साथ गठबंधन तोडने के अवसर बनाए गए। जाट तो 2014 से ही खट्टर-विरोधी रहे हैं। यहां तक कि पार्टी के अधिकांश विधायक ही उनके खिलाफ थे और पार्टी नेतृत्व के सामने विरोध जताते रहते थे, लेकिन तब तक प्रधानमंत्री की इच्छा खट्टर के पक्ष में थी और पार्टी ने लोकसभा की सभी 10 सीटें भी 2019 में जीती थीं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी वोट बैंक को लामबंद करते रहे हैं और उसमें उन्हें सफलता भी मिली है। पिछले आम चुनाव में ओबीसी के 45 फीसदी वोट भाजपा के पक्ष में आए, जो सर्वाधिक हैं।हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को राज्य की 30 फीसदी ओबीसी आबादी का चेहरा चित्रित किया जा रहा है, जबकि सैनी समुदाय की आबादी तो मात्र 2.9 फीसदी ही है। गैर-जाट, पिछड़े, दलित, पंजाबी, ब्राह्मण आदि अब भाजपा के 70 फीसदी से अधिक जनाधार हैं। यदि सरकार-विरोधी लहर मुख्यमंत्री खट्टर के कारण महसूस की जा रही है, तो उन्हीं की कैबिनेट के पांच चेहरों को दोबारा मंत्री क्यों बना दिया गया?

राय

क्यों पीनी पड़े शराब

कुछ तो शुक्रिया अदा शराब की बोतल का करें, जिसकी बदौलत प्रदेश का चूल्हा जलेगा। कोशिश हर बोतल से पूछ रही है कि इस बार कमाई के छबील पर कितना नशा बहेगा। ठेकेदारों की खिदमत में बोलियां लगाता आबकारी विभाग अपने सिर की जुएं निकाल देगा और फिर यूनिट दर यूनिट, इस महफिल में कमाने का जरिया, हमारी ही दरिद्रता के सामने अमीर हो जाएगा। पिछले दस महीनों में जिन लोगों ने नौ करोड़ से भी अधिक शराब की बोतलें गटक लीं, उनका शुक्रिया अदा करें या हर बोतल से निकलते मिल्क सेस का तिलक करें जिसने नब्बे करोड़ की उपज पैदा कर ली। सब कुछ ठीक व अनुमान पर खरा उतरा तो इस बार करीब 2100 शराब के ठेकों की नीलामी 2700 करोड़ की कमाई कर देगी और अब तो किराना दुकान पर राशन के एक कोने में बोतल इस्तकबाल करेगी। पीने वालों के लिए अब राशन की कतार में शराब की बोतल भी अवतार है। हर आबकारी नीति का भरोसा शराब की अधिकतम बिक्री पर है, इसलिए नए आविष्कार में किराने का कोना मधुशाला बनेगा और विभाग की खिचड़ी में शराब पकेगा। स्मार्ट लीकर शॉप, हमारी आर्थिकी के बुरे दिनों की साथी है और हर शराबी सरकार के खजाने के लिए गा रहा है, 'साथी हाथ बढ़ाना।' हो सकता है इस बहाने हिमाचल की रगों में बहती शराब, प्रदेश की खातिर बहती गंगा में हाथ धो ले। पाप को पुण्य में बदलने के लिए शराब की महती कोशिश की सराहना करें या कभी उस आईने में देखें जहां नैतिकता के हिसाब से कोई न कोई खानदान हार रहा होता है।

फिर सस्ती शराब के चटकारे लेने वालों का क्या कसूर जो नकली शराब की हांडी में मुंह मारकर आंतडियों में छाले पैदा कर लेते हैं। कितना महीन काम है शराब की बोतल पर नन्हें शब्दों में लिखना कि इसका सेवन करना हानिकारक है। बजट भले ही शराब पीने को प्रेरित नहीं करता, लेकिन गरीबी से बचाने के लिए कमाई का संतुलन पैदा करता है। अगर इस साल शराब पीने की आदत बढ़ जाए या एक बोतल पीने वाले एक साथ दो-दो पी लें, तो आबकारी विभाग की बल्ले-बल्ले हो जाएगी। जब से सभ्य समाज ने राज्य के बजट को करमुक्त देखना शुरू किया है, कमाई के लिए किसी को तो पीना ही पड़ेगा। कोई स्थानीय नगर निकाय के लिए, तो कोई दूध की खरीद बढ़ाने के लिए पी रहा है। जो ऐसा नहीं कर पा रहे, आज भी गुड़ की कच्ची शराब पीकर, सरकारी कमाई का गुड़ गोबर कर रहे हैं। हमें क्योंकि मुफ्त की बिजली चाहिए, सस्ते में पीने का पानी, कम किराए वाली बस, बिना बच्चों के मुफ्त पढ़ाई वाला स्कूल गांव में चाहिए, गरीब बनकर बीपीएल से सगाई चाहिए और सरकारी नौकरी में ओपीएस की शुमारी चाहिए, तो किसी को तो शराब पीनी होगी।

इसलिए कभी रात को हिमाचल का परिदृश्य में संभल कर देखना कि जो पीकर गिरा है, वह राज्य के कोष के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। यह उसकी हिम्मत है कि गुर्दे फेल होने तक प्रदेश के खजाने की चिंता में बोतल पर बोतल लिए मर रहा है। हम शराब बिक्री के आंकड़ों में करमुक्त बजट की फौलादी बाहें देखते हैं- कितनी शिद्दत से सरकारी वादों के अमन में बिकती हुई शराब हमेशा शांत दिखती है। आश्चर्य है कि शराब की बिक्री आज तक अस्पताल के बिस्तर पर बिखरी शराबी की जिंदगी नहीं देख पाई। जिसने पीकर खजाना भरा, उसके अभिशाप में परिवार के अरमान किस तरह जिंदा जले, प्रदेश नहीं देख रहा। काश, हम करमुक्त राज्य के बजाय शराबमुक्त राज्य होने की कीमत अदा करने के योग्य हो जाते। शराब की बिक्री बढ़ाने के बजाय, कर उगाही में प्रदेश को सम्मानित कर पाते।

दर्द भरे जिगर की आवाज

इस देश के लोगों को उन कतारों में खड़े होने की आदत हो गई है, जो आगे नहीं सरकती। वैसे कतारों में खड़े होने की आदत यहां है भी नहीं। कतार तोड़ कर आगे बढ़ जाने की धक्कमपेल है। धक्का-मुक्की यहां शूरवीरता मानी जाती है और चोर दरवाजे खोल कर गद्दी पर आसीन हो जाना नए युग का धर्म। फिर जो आसीन हो गया, वह नीचे उतरता कहां है। संन्यास लेने का वक्त आ जाए, तो भी देश की चिंता उसे इतना सताती है कि उसका संन्यास मुल्तवी होता जाता है। यहां त्याग और तपस्या एक मुखौटा बन गई है, और जीवन जीने का उपदेश देना एक रिवाज। जो जिंदगी जी नहीं पाए, वे अपनी असफलता को रण छोडऩा नहीं, अपनी त्याग भावना का प्रतीक मानते हैं। कला-संस्कृति की बात करने वाली उवाच प्रशस्ति के तराजुओं में तोल कर हर धान एक ही कीमत बिकता है। वह कीमत है, थोथा चना बाजे घना। बड़े आदमी के साथ फोटो खिंचवा कर फेसबुक से लेकर सांस्कृतिक समाचारों में घुसपैठ कर जाना एक ऐसा प्रिय शगुन है कि जिसे हर स्थापना का भी तलाशना है। यह स्थापना कहीं भी हो सकती है, केवल लेखन ही नहीं, खेल के मैदान में, खोज तलाश के अन्वेषण में और ऊंचे स्वर में चिल्ला कर उनकी ऐसी उपलब्धियों के चीखो-पुकार में जो कभी आपके पास फटकी नहीं। लेकिन उनकी प्राप्ति की घोषणा करने में आपने कभी कमी नहीं की। वैसे जब आर्थिक प्रगति के दावे हों तो लगता है ऊंची अटारियों वालों के घर और भी ऊंचे हो गए और गूदड़ बस्तियों के क्रंदन को कोई सुनता नहीं। संघर्ष, प्रगति और निरंतर चलते रहना कितने अच्छे शब्द लगते हैं, लेकिन उनका खोखलापन अजनबी नहीं लगता। क्योंकि यहां संघर्ष का अर्थ है रेंगना, प्रगति का अर्थ खोखले आंकड़ों का मायाजाल और निरंतर चलते रहने का अर्थ है एक ही वृत्त में निरंतर गोलाकार घूमते रहना। यहां रोज परिभाषाएं बदल जाती हैं। यहां समाजवाद को उल्टे रास्ते से पकडने का प्रयास शुरू हो गया। पहले कहते थे निर्धन और वंचित को रोजी, रोजगार और धनियों के अनावश्यक शोषण पर रोक ही नए समाज का निर्माण करेगी। लेकिन बंधु, समाज का निर्माण तो हुआ नहीं, बल्कि अरबपतियों के धन बढ़ाने का रिकार्ड बनने लगा, नई ऊंचाइयां मिलने लगीं। लीजिये सब पुराने रास्ते दरकिनार हो गए और सार्वजनिक क्षेत्र को नौकरशाही का पुलिंदा कह कर नकारा जाने लगा, अब उसके स्थान पर निजी क्षेत्र को तरक्की का जामिन बना दिया गया, प्रगति दर के बढने का ऊंचा मीनार बता दिया गया। आज लाखों हाथ नौकरी मांगते हैं, टूटे हुए हाथों को अपना हाथ जगन्नाथ का उपदेश मिल गया। योजनाबद्ध आर्थिक विकास की पंचवर्षीय योजना का आसरा लेकर आर्थिक विकास की दर वहां पहुंचा देनी थी, जहां अर्थव्यवस्था स्वतः स्फूर्त कहला देती थी। लेकिन यह कैसा स्वतः स्फूर्त कि देश का उत्पाद चौबीस प्रतिशत घट गया और आर्थिक विकास दर शून्य से भी सात प्रतिशत नीचे गिर कर शर्मिन्दा हो गई। इन योजनाओं को बनाने वाला योजना आयोग सफेद हाथी करार दे दिया गया। अब उसकी जगह प्रगट हुआ नीति आयोग, जिसकी नीति की तलाश हो रही है और आयोग के सदस्य किंकत्र्तव्यविमूढ़ हैं कि नई योजना बनाएं या इसे भी निजी क्षेत्र की सरदारी के हवाले कर दें? बड़े आंकड़ों की इस दुनिया में महामारी में हर देने वाली दवाइयों की घोषणा होती है तो लोग उसकी खाली और प्रयुक्त शीशियों की तलाश में जुट जाते हैं। दवा के ऐसे पाऊडर बना इनमें भरे जाते हैं, जो बुखार के भरोसे छोड़ उस पर नित्य नई विजय प्राप्त कर लेने की घोषणा करते हैं। लेकिन यह सब चलता ही रहता है। लोगों को तो अच्छे दिनों के नाम पर यह सब भुगतने की आदत हो गई है।

विचार

पर्यटन प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बने हिमाचल

मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार तक इस लेख के माध्यम से विकास एवं पर्यटन संभावनाओं में बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत कुछ ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान अपर्याप्त सुविधाओं की कहानी एवं मांग को पहुंचाने की कोशिश की है ताकि राज्य सरकार व्यावसायिक तौर-तरीके अपनाकर हिमाचल की पर्यटन आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए काम करे

पर्यटन मंत्रालय की पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 से यह खुलासा हुआ है कि वर्ष 2022 में 85.9 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए। इनमें सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित कर गुजरात शीर्ष पर रहा। गुजरात में कुल 17.8 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे तो महाराष्ट्र में 15.1, पश्चिम बंगाल में 10.4, दिल्ली में 8.2 और उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख विदेशी पर्यटकों ने दस्तक दी। हमारे देश में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक अमरीका से आते हैं। उसके बाद पड़ोसी बांग्लादेश से पधारते हैं। आंकड़ों की बानगी से देखें तो वर्ष 2022 में अमरीका से 22.19 फीसदी, बांग्लादेश से 20.29 फीसदी, ब्रिटेन से 9.98 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया से 5.96 प्रतिशत और कनाडा से 4.48 प्रतिशत विदेशी पर्यटक भारत आए। वहीं हम हिमाचल में कुल विदेशी और देसी पर्यटकों की आमद का विश्लेषण करें तो वर्ष 2023 में भारतीय पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वर्ष 2023 में 62806 विदेशी पर्यटक, 1.59 करोड़ से अधिक भारतीय पर्यटकों ने हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया था। चूंकि दूसरे राज्यों के मुकाबले हिमाचल आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या मामूली सी नजर आती है, लिहाजा विदेशी पर्यटकों को हिमाचल आने और लुभाने के लिए पर्यटन विभाग को व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर में बढ़ती पर्यटकों की संख्या के दृष्टिगत भी हिमाचल से पर्यटकों के खिसकते आधार को पुख्ता बनाने की जरूरत है।

हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन कारोबार का योगदान करीब 9 प्रतिशत है। लिहाजा हिमाचल आने वाले पर्यटकों को सस्ती एवं बेहतरीन सुविधाएं देने की खास आवश्यकता है। इसके लिए हिमाचल सरकार को न केवल पर्यटन सेवाओं का विस्तार और नियोजन करना होगा, अपितु उन कारणों का निवारण भी करना होगा कि किस प्रकार से पर्यटन निगम की होटल इकाइयों की कार्यप्रणाली को उत्तम सेवा प्रदाता संस्था बनाकर उसे लाभप्रद एवं लोकप्रिय बनाया जा सके। वर्तमान में पर्यटन विकास निगम प्रदेश में 55 होटलों का संचालन कर रहा है। इनमें से 24 लाभ में और 31 घाटे में चल रहे हैं। पर्यटन विभाग को दूसरे राज्यों के बेहतरीन एवं फायदे में चल रहे पर्यटन विकास निगमों के होटलों का तुलनात्मक सर्वे करवा कर वहां के मॉडल को हिमाचल में लागू करना चाहिए। यह अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश सरकार साहसिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है और भविष्य में सालाना पांच करोड़ पर्यटकों का स्वागत करने का लक्ष्य है। सरकार की एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की सहायता से पर्यटन विकास पर 2500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इसके साथ ही राज्य के सभी सरकारी विश्राम गृहों को ऑनलाइन रिजर्वेशन के द्वारा पर्यटकों के लिए खोलना चाहिए ताकि सरकार की आमदनी में बढ़ोत्तरी हो। हिमाचल पर्यटन विकास निगम के लगभग सभी कर्मचारी कुशल, विनम्र और व्यवहार कुशल हैं। लेकिन यदि आप किसी वेटर अथवा अन्य कर्मचारी से उनकी स्थायी नौकरी बारे जानकारी लेंगे तो आउटसोर्स कर्मचारी होने का उनका दर्द उनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से उभर आता है। जाहिर है कि सरकार ही जब बेरोजगारों की मजबूरी का लाभ उठाने की फिराक में रहेगी, तो भला प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कामगारों को कहां उचित वेतन-भत्ते मिलेंगे। महंगाई के इस दौर में 10-12 हजार की मामूली तनख्वाह में महीने भर का गुजारा कैसे होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है।

लडक़ों की तो शादियां होने से रहीं, क्योंकि आजकल लड़कियां सबसे पहले वेतन और पैकेज के बारे में तहकीकात करती हैं। सरकार माई-बाप है और उसे कम से कम प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले सरकारी नौकरियों में जीवनयापन लायक वेतन-भत्तों और पेंशन की गारंटी देकर अपने कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करना ही चाहिए, ताकि कर्मचारी जोश और जज्बे के साथ अपनी सेवाएं मुस्कुराते हुए दे सकें। राज्य पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली कहते भी हैं कि हिमाचल प्रदेश में आधुनिक पर्यटन की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और कांगड़ा जिले पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रघुबीर सिंह बाली ने घोषणा की है कि फौज में सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को निगम के होटलों में रहने पर पचास फीसदी की छूट दी जाएगी। यह सुविधा उन्हें साल के आठ महीने मिलेगी, जबकि मार्च से लेकर जून के चार महीने तक उन्हें 30 फीसदी की छूट दी जाएगी। साथ ही होटल में रहने वाले फौजियों को खाने पर अतिरिक्त से 30 फीसदी की छूट दी जाएगी। मेरा सुझाव है कि इस सुविधा को भारत के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए भी बढ़ाया जाना चाहिए।

यह अच्छी बात है कि 01 फरवरी को केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने राज्यों को पर्यटन केंद्रों के व्यापक विकास और दुनियाभर में उनकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता देने का आश्वासन दिया है। इन पर्यटन केंद्रों पर सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग भी दी जाएगी और साथ ही राज्यों को ब्याजमुक्त लोन दिया जाएगा ताकि पर्यटन क्षेत्रों का विकास हो सके। पर्यटन सेवाओं के पूर्णतः व्यवसायीकरण से ही हम बेहतरीन नतीजे हासिल कर सकते हैं। मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार तक इस लेख के माध्यम से विकास एवं पर्यटन संभावनाओं में बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत कुछ ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान अपर्याप्त सुविधाओं की कहानी एवं मांग को पहुंचाने की कोशिश की है ताकि राज्य सरकार व्यावसायिक तौर-तरीके अपनाकर हिमाचल की पर्यटन आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए काम करे। तभी हिमाचल पर्यटन प्रतिस्पद्र्धा में अग्रणी राज्यों में निश्चित रूप से शुमार होगा।

सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बढ़ाई राशि, अब लाभार्थी को मिलेंगे इतने पैसे

भारत सरकार के साथ राज्य सरकार भी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कई तरह की स्कीम चला रही है। उत्तर-प्रदेश सरकार बेटियों के लिए **Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana** चला रही है। अब यूपी सरकार ने इस योजना में मिल रही राशि को बढ़ा दिया है। चलिए जानते हैं कि अब लाभार्थी को कितने पैसे मिलेंगे।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana) की राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। सरकार ने ग्रांट अमाउंट में 10,000 रुपये का इजाफा किया है।

सरकार ने पहले इस योजना में ग्रांट अमाउंट 15,000 रुपये तय की थी जो वित्त वर्ष 2024-25 से 25,000 रुपये हो जाएगी। बता दें कि इस स्कीम के तहत सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनके ग्रेजुएशन या डिप्लोमा तक वित्तीय सहायता देती है। यह राशि किस्तों में मिलती है। अब जब ग्रांट अमाउंट में बढ़ोतरी हुई है तो योजना के किस्तों में भी बदलाव हो गया है।

अब कितना मिलेगा पैसा

यूपी सरकार के आदेश के अनुसार योजना में शामिल बेटी को पहली किस्त में 2,000 रुपये मिलते थे जो अब बढ़कर 5,000 रुपये हो गए हैं। जब बेटी 2 साल की हो जाती है तो उसे दूसरी किस्त मिलती है।

इसमें भी बेटी को 2,000 रुपये का लाभ मिलेगा। बेटी के पहली कक्षा में दाखिल होने के बाद सरकार 3,000 रुपये की तीसरी किस्त देगी।

इसके बाद जब बेटी कक्षा छह में प्रवेश करेगी तो सरकार 3,000 रुपये का लाभ देगी। पांचवी किस्त बेटी की 9वीं कक्षा में प्रवेश होने के बाद मिलेगा। 5वीं किस्त में बेटी को 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। छठी किस्त तब मिलेगी जब बेटी स्कूल से पास हो जाएगी।

स्कूल उत्तीर्ण होने के बाद सरकार 5,000 रुपये की राशि मिलेगी। आखिरी किस्त में बेटी को 7,000 रुपये का दिये जाएंगे।

सरकार ने यह योजना बेटियों को शिक्षित करने के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की है। इसमें सरकार बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक का पूरा खर्च उठाती है।

महाराष्ट्र सरकार ने 1601 करोड़ रुपये में खरीदी Air India की बिल्डिंग, जानें क्यों खास रही यह डील

महाराष्ट्र सरकार ने Air india की बिल्डिंग को 1601 करोड़ रुपये में खरीदा। 2012 में दक्षिण मुंबई में राज्य सचिवालय भवन में आग लग गई थी। आग लगने के बाद से सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा जल आपूर्ति और स्वच्छता और ग्रामीण विकास का संचालन जीटी अस्पताल से हो रहे था। अब इन सभी विभाग को एयर इंडिया बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

नई दिल्ली। एयर इंडिया बिल्डिंग का मालिकाना हक महाराष्ट्र सरकार को मिल गया है। केंद्र सरकार ने संपत्ति हस्तांतरण को मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के नरीमन पॉइंट पर एयर इंडिया की इमारत को 1,601 करोड़ रुपये में खरीदा।

दीपम सचिव तुहिन कांता पांडे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत सरकार ने एआई एसेट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (AIAHL) की एयर इंडिया बिल्डिंग, मुंबई को 1601 करोड़ रुपये पर महाराष्ट्र सरकार (GOM) को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। जीओएम 298.42 करोड़ रुपये का बकाया माफ करने पर सहमत हो गया है। इस लेनदेन के लिए एआईएएचएल द्वारा जीओएम को भुगतान किया जाएगा।

AIAHL कंपनी भारत सरकार की है। ये कंपनी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर आती है। इस कंपनी की स्थापना 2019 में एयर इंडिया की गैर-प्रमुख संपत्तियों और डेट को रखने के लिए की गई थी।

जमीन और बिल्डिंग सहित एयर इंडिया की गैर-प्रमुख संपत्ति को एआईएएचएल को हस्तांतरित कर दिया गया था। इसका मूल्य 14,718 करोड़ रुपये है। से सरकार द्वारा डेट और गैर-प्रमुख संपत्तियों को रखने के लिए एयर इंडिया की बिक्री के अग्रदूत के रूप में स्थापित किया गया था।

सरकार ने 27 जनवरी, 2022 को एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा समूह (Tata Group) को हस्तांतरित कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया को खरीदने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी।

क्यों खरीदी गई ये बिल्डिंग

1974 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर निर्मित, इस इमारत का उपयोग अब इसके कार्यालय स्थान के रूप में किया जाएगा। 23 मंजिला इमारत में सरकारी कार्यालयों के लिए लगभग 46,470 वर्ग मीटर जगह उपलब्ध होगी। 2012 में दक्षिण मुंबई में राज्य सचिवालय भवन में आग लगने के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता, और ग्रामीण विकास का संचालन जीटी अस्पताल से हो रहे हैं।

क्या होता है पिंक टैक्स? बायोकॉन फाउंडर किरन मजूमदार शा का पोस्ट हुआ वायरल, बोली- यह भेदभाव क्यों

महिलाओं के उत्पाद पर पिंक टैक्स लगाया जाता है। पिंक टैक्स एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। भारतीय फार्मास्युटिकल दिग्गज बायोकॉन (Biocon) की फाउंडर किरण मजूमदार-शॉ (Kiran Mazumdar Sha) ने पिंक टैक्स को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। पिंक टैक्स एक वैश्विक मुद्दा है। इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

नईदिल्ली। भारतीय फार्मास्युटिकल दिग्गज बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार-शॉ ने पिंक टैक्स (Pink Tax) को लेकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया जिसके बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिंक टैक्सस्र, एक भेदभावपूर्ण प्रथा है, जहां महिला उत्पादों की कीमत अक्सर पुरुषों के समान वस्तुओं की तुलना में काफी अधिक होती है। मजूमदार-शॉ का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। किरण ने अपने पोस्ट में मीडिया पर्सनैलिटी डॉ. संजय अरोड़ा का वीडियो को पोस्ट किया। डॉ संजय ने अपने वीडियो में महिलाओं और पुरुषों के प्रोडक्ट की कीमतों के अंतर को उजागर किया है। उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि महिलाओं के लिए एक लिप बाम 35% अधिक, एक प्लेन रेजर 10% अधिक, और एक साधारण टी-शर्ट 50% तक अधिक कीमत पर मिलती है। डॉ. संजय अरोड़ा ने बताया कि एक ही ब्रांड में जहां महिलाओं के लिप बाम की कीमत 250 है तो वहीं पुरुष के लिप बाम की कीमत 150 रुपये है। डॉ. अरोड़ा अपने वीडियो में महिलाओं पर हो रहे अन्याय पर प्रकाश डाला है। वह कहते हैं कि महिलाएं, जो पहले से ही एक महत्वपूर्ण वेतन अंतर का सामना कर रही हैं, केवल अपने लिंग के कारण बुनियादी आवश्यकताओं के लिए बढ़ी हुई कीमतों का भुगतान करने के लिए मजबूर हैं।

ग्लोबल प्रॉब्लम है "Pink Tax"

पिंक टैक्स केवल भारतीय मुद्दा नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन में हुए अध्ययन से पता चलता है कि महिलाओं की व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं पुरुषों की तुलना में नियमित रूप से अधिक महंगी होती हैं। इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग जैसी सेवाओ में भी महिलाओं के कपड़ों पर ज्यादा शुल्क लगता है।

आसमान छू रहे हैं सोने-चांदी के भाव, आपके शहर में इतने रुपये महंगा हुआ गोल्ड

Gold-Silver इस हफ्ते सोने की कीमतों में तेजी आई है। आज जहां एक तरफ सोना 250 रुपये महंगा हुआ तो वहीं चांदी के दाम में 1000 रुपये से ज्यादा ती तेजी देखने को मिली है। गोल्ड के कीमत रिकॉर्ड स्तर के पार पहुंच गई है। ऐसे में आपको सोना खरीदने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि आपके शहर और बाकी शहर में कितने रुपये में गोल्ड मिल रहा है।

नई दिल्ली। आज भी सोने के साथ चांदी की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। इस हफ्ते लगातार सोने की कीमतों में उछाल आया है। आज सोना 250 रुपये चढ़ा है तो चांदी की कीमत में 1200 रुपये की तेजी आई है।

गोल्ड और सिल्वर की कीमत कई शहरों में अलग होती है। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स की वजह से हर शहर में इनकी कीमत अलग होती है। चलिए, जानते हैं कि आज आपके शहर में सोने कितने रुपये ग्राम है।

चेक करें आज के लेटेस्ट रेट

गुड रिटर्न के मुताबिक, आपके शहर में सोना-चांदी के लेटेस्ट रेट्स-

दिल्ली में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,260 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,110 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,110 रुपये है।

चेन्नई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,930 रुपये है।

हैदराबाद में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,110 रुपये है।

चंडीगढ़ में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,260 रुपये है।

जयपुर में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,260 रुपये है।

पटना में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 66,160 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 66,260 रुपये है।

नागपुर में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 66,110 रुपये है।

सूरत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 66,160 रुपये है।

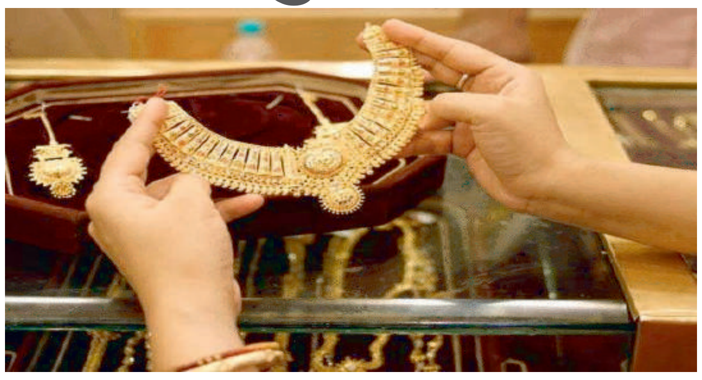

पुणे में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 66,160 रुपये है।

केरल में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 66,110 रुपये है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 66,110 रुपये है।

गोल्ड और सिल्वर का स्पॉट प्राइस

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटी के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा

दिल्ली के बाजारों में सोने की हाजिर कीमतें (24 कैरेट) 66,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही हैं, जो पिछले बंद से 250 रुपये अधिक है। अमेरिकी डॉलर में गिरावट और सुरक्षित निवेश के कारण खरीदारी के कारण गुरुवार को यूरोपीय कारोबारी सत्र के दौरान सोने की कीमतें हाल के निचले स्तर से उबर गईं और ऊंची हो गईं।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, कॉमेक्स पर सोना हाजिर 2,169 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद से 9 अमेरिकी डॉलर अधिक है। चांदी भी बढ़कर 24.92 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई और पिछले कारोबार में यह 24.22 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई थी।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतों में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को सोने की कीमतें 250 रुपये बढ़कर 66,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं।

वायदा कारोबार में सोना-चांदी

वायदा कारोबार में सोना पुरानी कीमतें 165 रुपये घटकर 65,730 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 165 रुपये या 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 65,730 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई, जिसमें 15,945 लॉट का कारोबार हुआ।

वायदा कारोबार में गुरुवार को चांदी की कीमत 90 रुपये बढ़कर 75,260 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, मई डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 90 रुपये या 0.12 प्रतिशत बढ़कर 25,003 लॉट में 75,260 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।

गौतम अडानी ने हिंडेनबर्ग रिपोर्ट को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा - हमें और देश को बदनाम करने की थी साजिश

भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) को लेकर कहा कि रिपोर्ट में लगाए गए आरोप का असर केवल अदाणी ग्रुप (Adani Group) पर ही नहीं बल्कि भारत की शासन प्रथाओं को भी बदनाम किया है। जनवरी 2023 में अदाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था। हालांकि इस साल सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप्स पर लगे सभी आरोपो को गलत ठहरा दिया।

नई दिल्ली। जनवरी 2024 को अदाणी ग्रुप (Adani Group) को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट (Hindenburg Report) आई थी। इस रिपोर्ट में अदाणी ग्रुप पर नियमों के अनुपालन और शेयरों की हेराफेरी का आरोप लगाया था।

इस आरोप का असर अदाणी ग्रुप के मार्केट कैप से लेकर कंपनी के शेयर पर पड़ा। हालांकि, इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी पर लगने वाले आरोप को गलत ठहरा दिया।

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कहा कि अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने न केवल अदाणी ग्रुप को ही नहीं बल्कि भारत के शासन प्रथाओं को भी बदनाम किया है।

जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अदाणी ग्रुप पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में आयात लागत का अधिक बिल बनाना और शेयर की कीमतें बढ़ाने जैसे आरोप शामिल थे। हालांकि, गौतम अदाणी ने इन सभी आरोपों से इंकार कर दिया था।

इस साल सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप को राहत की सांस दी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि अब अदाणी ग्रुप पर तिरिक्त जांच का सामना करने की आवश्यकता नहीं है।

अदाणी ग्रुप के शेयर प्राइस पर पड़ा असर

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर अदाणी ग्रुप के सभी कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला था। रिपोर्ट के आने के बाद अदाणी ग्रुप के स्टॉक में लगभग 150 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की बिकवाली हुई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने से पहले गौतम अदाणी दुनिया के सबसे अमीर लिस्ट में शामिल था वो बाद में दुनिया के टॉप-20 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए।

वर्तमान में अदाणी ग्रुप ने शेयरों में हुए नुकसान की भरपाई कर ली है।

गौतम अदाणी ने एक निजी कार्यक्रम में अपने जीवन यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने अवसरों और चुनौतियों के बारे में बताया।

गौतम अदाणी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कहा कि पिछले साल 24 जनवरी को हमें एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर द्वारा बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया था। इसका उद्देश्य सिर्फ हमें अस्थिर करना नहीं था बल्कि भारत की शासन प्रथाओं को राजनीतिक रूप से बदनाम करना भी था।

शेयरों में आई गिरावट को लेकर अदाणी ने कहा कि शेयरों में कमी आने से हमें सीख भी मिली है। ये हमारी रिकवरी को मजबूत होकर वापसी करने के सार को उजागर करती है। हमने गिरावट के बाद उठने की भावना का प्रतीक है।

कैसा रहा गौतम अदाणी का सफर

गौतम अदाणी ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने एक कमोडिटी बिजनेस के रूप में शुरुआत की और बंदरगाहों, पावर प्रोडक्शन, हवाई अड्डों, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा, गैस, डेटा सेंटर, मीडिया और सीमेंट तक फैले साम्राज्य के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए।

वह कहते हैं कि उद्यमिता जोखिम लेने और कभी खोने, कभी गिरने के साथ ठीक रहने के बारे में है। वह कहते हैं कि हर बार जब मैं खो गया - हर बार मैं गिर गया - मैं अभी भी अपना रास्ता खोजने में सक्षम था। मैं अभी भी उठने में सक्षम था। मैं कभी नहीं डरा।

गौतम अदाणी के पांच सिद्धांत

सफलता के साथ चुनौतियां भी साथ आएगी। वह कहते हैं कि आपकी सफलता जितनी बड़ी होगी, आपका लक्ष्य उतना ही बड़ा होगा।

हम एक जटिल दुनिया में रहते हैं और सादगी के सिद्धांत पर बेचा जाना आसान है। हालांकि सादगी लक्ष्य हो सकती है, लेकिन यह जटिलता को प्रबंधित करने की क्षमता है।

अदाणी ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए एक गतिशील मॉडल के साथ लचीले दृष्टिकोण की आवश्यकता है। रणनीतिक भेदभाव का मूल समझने के लिए किताबी ज्ञान और पश्चिम-केंद्रित मॉडल की सीमाओं को समझने की आवश्यकता है।

लचीलेपन के लिए अक्सर आलोचना झेलने की क्षमता की आवश्यकता होती है। आप जितना ऊपर उठेंगे, उतना ही आपको आलोचना को संभालने के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता होगी। अदाणी ने कहा कि किसी को गलत समझे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

अदाणी कहते हैं कि आपकी अपनी सफलता आपकी विनम्रता को पीछे धकेल देगी। लेकिन विनम्रता ही सबसे बड़ा अंतर है जिसे आप विकसित कर सकते हैं।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र समेत कई PSU बैंक सरकार की हिस्सेदारी कम करने की बना रहे योजना

देश के कई बैंक सरकारी हिस्सेदारी को 75 प्रतिशत से कम करने की योजना बना रहे हैं। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र आईओबी और यूको बैंक सहित पांच पब्लिक सेक्टर के बैंक शामिल हैं। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने बताया कि 12 पब्लिक सेक्टर के बैंकों में से चार 31 मार्च 2023 तक एमपीएस मानदंडों का अनुपालन कर रहे थे। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी और यूको बैंक सहित पांच पब्लिक सेक्टर के बैंक न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों का पालन करने के लिए सरकारी हिस्सेदारी को 75 प्रतिशत से कम करने की योजना बना रहे हैं।

12 पब्लिक सेक्टर के बैंकों (पीएसबी) में से चार 31 मार्च, 2023 तक एमपीएस मानदंडों का अनुपालन कर रहे थे।

विवेक जोशी ने पीटीआई एजेंसी को बताया कि तीन से ज्यादा पीएसबी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 25 प्रतिशत सार्वजनिक फ्लोट का अनुपालन किया है। बाकी पांच पीएसबी ने एमपीएस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई हैं।

किस बैंक की कितनी है हिस्सेदारी

दिल्ली स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 98.25 फीसदी है। इसके बाद चेन्नई स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक 96.38 प्रतिशत, यूको बैंक 95.39 प्रतिशत, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 93.08 प्रतिशत, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 86.46 प्रतिशत है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार, सभी सूचीबद्ध कंपनियों को 25 प्रतिशत का एमपीएस बनाए रखना होगा। हालाँकि, नियामक ने राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को विशेष छूट दी थी। उनके पास 25 प्रतिशत एमपीएस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगस्त 2024 तक का समय है।

जोशी ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो की समीक्षा करने का निर्देश दिया है क्योंकि नियामक मानदंडों का अनुपालन न करने के मामले सरकार द्वारा देखे गए हैं।

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने पीएसबी के प्रमुखों को संबोधित एक पत्र में उनसे गोल्ड लोन से संबंधित अपनी सिस्टम और प्रक्रियाओं पर गौर करने को कहा है। इस संबंध में एक निर्देश पिछले महीने जारी किया गया था जिसमें उन्हें शुल्क और ब्याज के संग्रह और गोल्ड लोन अकाउंट को बंद करने से संबंधित विसंगतियों को ठीक करने की सलाह दी गई थी।

डीएफएस ने बैंकों से 1 जनवरी, 2022 से 31 जनवरी, 2024 तक पिछले दो साल की अवधि की गहन समीक्षा करने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी गोल्ड लोन बैंकों की नियामक आवश्यकताओं और आंतरिक नीतियों के अनुपालन में वितरित किए गए थे।

योजना के तहत बैंक फाइनेंस के अलावा ई ऑटो रिक्शा पर 50 हजार रुपए तक की सब्सिडी का भी मिल रहा

प्रदेश में ई ऑटो रिक्शा की ड्राइविंग सीट संभालेंगी महिलाएं

एमएसएमई द्वारा संचालित और यूपिकॉन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को किया जा रहा क्रियान्वित । प्रशिक्षण के साथ ही महिलाओं को पिंक किट और बैंक फाइनेंस की सुविधा तक प्रदान की जा रही

परिवहन विशेष न्यूज

लखनऊ। रोडवेज बसों के बाद अब उत्तर प्रदेश की महिलाएं आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी ड्राइविंग सीट पर नजर आने वाली हैं। प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में जुटी योगी सरकार मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को स्वरोजगार उन्मुख ई रिक्शा प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ रही है। इसके माध्यम से सरकार न सिर्फ महिलाओं को निशुल्क ई रिक्शा प्रशिक्षण दिला रही है, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही सस्ती ब्याज दरों पर ई रिक्शा दिलाने का भी प्रबंध कर रही है। यही नहीं, ई रिक्शा पर 50 हजार रुपए तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। प्रत्येक जनपद से 250 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार की इस पहल से अब प्रदेश भर में सड़क पर प्रशिक्षित महिला ड्राइवर्स उच्च गुणवत्ता वाले ई रिक्शा चलाती नजर आएंगी। इससे उनकी आय का प्रबंध भी होगा और रोड एक्सीडेंट जैसी घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा।

करीब 20 हजार महिलाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण

यूपीकॉन के एमडी प्रवीण सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत ई रिक्शा प्रशिक्षण कार्यक्रम एमएसएमई विभाग द्वारा संचालित एवं यूपीकॉन द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद से एक हजार महिलाओं को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है। मिशन शक्ति के तहत दो पार्ट में ट्रेनिंग आयोजित की गई है। पहले चरण में 56200 महिलाओं (प्रति जनपद 750) को 6 दिन का प्रशिक्षण दिया गया था। इसमें तीन दिन महिलाओं के वर्क प्लेस से संबंधी सेफ्टी, सिक्योरिटी, और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद तीन दिन उनको उद्यमिता विकास की ट्रेनिंग कराई गई थी। फेज 2 में 250 महिलाएं प्रति जनपद के हिसाब से 18750 महिलाओं को ई रिक्शा ट्रेनिंग दी जा रही है। ड्राइविंग डोमेन में स्वरोजगार उन्मुख प्रशिक्षण की अवधि 6 माह की है। प्रशिक्षण के लिए महिलाओं का चयन मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइंस के तहत किया जा रहा है। इसमें 10वीं पास 18 से 40 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। साथ ही उनके पास आधार और पैन कार्ड होना अनिवार्य है।

महिलाओं को दी जा रही पिंक ड्रेस एवं सेफ्टी किट

उन्होंने बताया कि यह एक लाइवलीहुड प्रोग्राम है। इसके तहत हमने 250 महिलाएं प्रति जनपद का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 250 महिलाओं का चयन करेंगे और फिर उनको ई रिक्शा स्वरोजगार उन्मुख करेंगे। चयन के बाद महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें क्लास रूम ट्रेनिंग भी है जिसमें उन्हें ई रिक्शा और ड्राइविंग रूल्स के विषय में बताया जा रहा है। इसके बाद उनको प्रैक्टिकली ई रिक्शा चलाना सिखाया जा रहा है। महिलाओं को ई रिक्शा की पिंक ड्रेस भी दे रहे हैं एवं सेफ्टी किट और स्टेशनरी किट भी प्रदान की जा रही है। इसके बाद महिलाओं को आरटीओ के सहयोग से ड्राइविंग लाइसेंस भी दिलाने में मदद की जा रही है। फाइनली उनको बैंक तक ले जाने का प्रॉसेस भी हम करा रहे हैं। इसमें सुनिश्चित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का जो लाभ है वो महिलाओं को मिल सके, जिसमें बैंक से आसान लोन भी शामिल है।

स्वरोजगार शुरू कराने में भी की जा रही मदद

प्रवीण सिंह ने बताया कि योजना के तहत ई रिक्शा की स्टैंडर्ड कॉस्ट 1.98 लाख रुपए निर्धारित की गई है। हमने जेम पोर्टल के माध्यम से ई रिक्शा कंपनीज का चयन किया है। ये कंपनियां लिथियम आयन बैटरी वाले ई रिक्शा बनाती हैं जो सबसे उच्चतम क्वालिटी के होते हैं। 1.98 हजार में योजना के अंतर्गत योग्य पाई जाने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 49 हजार 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। बाकी जो पैसा है उसको नेशनलाइज बैंक से फाइनेंस कराने का प्रयास किया जाएगा। हमारा प्रयास महिलाओं को बैंक तक ले जाना और उनका फाइनेंस कराना है, ताकि उनका स्वरोजगार शुरू हो सके। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम नवंबर 2023 से शुरू हुआ है। अभी बैचवार यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें एक बैच में प्रति जनपद 250 महिलाओं का प्रशिक्षण चल रहा है। जिन जनपदों में पोटेंशियल ज्यादा है, वहां संख्या ज्यादा भी की जा सकती है।

योजना से महिलाओं का हो रहा सशक्तिकरण

इस परियोजना का उद्देश्य चयनित महिला उम्मीदवारों को उपयुक्त कौशल और महिला सुरक्षा, सुरक्षा उपायों और समाज में सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स के बारे में ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। साथ ही उन्हें सुरक्षित रूप से यात्रा करने में मदद करके समाज की अन्य महिलाओं की मदद करने के लिए सशक्त बनाना और उन्हें अन्य महिलाओं के लिए एक आदर्श मॉडल बनने में सक्षम बनाना है। यही नहीं समाज की समस्त महिलाओं को सुरक्षित वातावरण बनाने और एक उद्यमी बनने का प्रयास करने के लिए कार्यक्रमों का हिस्सा बनना भी शामिल है।

भाजपा जिलाध्यक्ष मेवाड़ा ने की विधानसभा प्रभारियों की घोषणा

परिवहन विशेष अनुपम शर्मा

भीलवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देशानुसार एवं जिला संगठन प्रभारी रतनलाल गाडरी एवं लोकसभा सह प्रभारी गजपाल सिंह राठौड़ के मार्गदर्शन में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने जिले में संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन हेतु संगठन विस्तार करते हुए सातों विधानसभाओं में प्रभारियों की घोषणा की है। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि जिलाध्यक्ष मेवाड़ा ने आसींद में विट्ठल शंकर अवस्थी, मांडल में नरेश सांड, सहाड़ा में शंकर गुर्जर, भीलवाड़ा में मदन भंडारी, शाहपुरा में रूपलाल जाट, जहाजपुर में बद्रीप्रसाद गुरुजी, मांडलगढ़ में राजेंद्रसिंह खामोर को विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति से संगठन मजबूत होगा। केंद्र व प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को भी विधानसभाओं में और अधिक गति मिलेगी।

वरिंदर फूल ने अमृतसर लोकसभा सीट से ठोंकी दावेदारी

अमृतसर (साहिल बेरी)। आईसीसी ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र फूल ने अमृतसर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी जताई है। वरिंदर फूल ने कहा कि वह आगामी लोकसभा चुनाव अमृतसर से लड़ना चाहते हैं और इस बारे में कांग्रेस हाईकमान को विचार करना चाहिए। वरिंदर फूल ने कहा के वह पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस के झंडे तले अलग-अलग पदों पर हर चुनाव में पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि एआईसीसी ह्यूमन राइट्स इस समय 26 राज्यों में काम कर रही है, 500 से ज्यादा जिले कवर है और सारे हिंदुस्तान में ढाई लाख से ज्यादा कार्यकर्ता है, अगर हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को 30, 30 वोट भी डलवाता है तो पार्टी को 75 लाख वोट का फायदा होता है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान एआईसीसी ह्यूमन राइट्स को कांग्रेस के छोटे संगठनों को शामिल करने की इजाजत देती है तो एआईसीसी ह्यूमन राइट्स कांग्रेस पार्टी को एक करोड़ से ज्यादा वोटो का समर्थन दिला सकती है। जहां बात रही अमृतसर की अमृतसर में एआईसीसी ह्यूमन राइट्स 650 से ज्यादा गांव और कॉर्पोरेशन की 85 वार्डों में अपने चार-चार प्रधान बना चुकी है और एआईसीसी ह्यूमन राइट्स के पास हर गांव में महिला बॉडी यूथ बॉडी और माइनॉरिटी सहित हर जगह 80 से ऊपर पदाधिकारी है। एआईसीसी ह्यूमन राइट्स घर से कम से कम 2 लाख वोट लेकर निकलते हैं और कांग्रेस की जीत अमृतसर से पक्की हो जाती है। अगर आईसीसी ह्यूमन राइट्स को अमृतसर की टिकट मिलती है तो पार्टी को उसका फायदा सारे हिंदुस्तान में एआईसीसी ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता से मिलेगा जिससे कांग्रेस और भी मजबूत होगी। इस मौके राज्य सैक्रेटरी महिला विंग किरण शर्मा, महासचिव अजय दवेसर, संजीव बिल्ला पी.ए, राज कुमार बोबी, निर्मल नीटा, कंवलजीत बल्लू, पवन चावला, अशोक कुमार, बलविंदर किशन, अमोद सिंह, पुनीत शर्मा, सुखदेव सिंह चब्बा आदि उपस्थित थे।

माह के द्वितीय गुरुवार को जिले में उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई का बनेडा में हुआ आयोजन

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं और समस्याओं की सुनवाई कर त्वरित समाधान के लिए माह के द्वितीय गुरूवार को आयोजित उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई के तहत जिला कलक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ज़िले के बनेडा उपखंड में आयोजित जनसुनवाई में पहुँचे। बनेडा में आयोजित जनसुनवाई में जिला कलक्टर शेखावत ने राजस्व, अतिक्रमण, विद्युत, महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के सम्पर्क पोर्टल पर 18 लम्बित परिवादों की एक - एक करके समीक्षा कर 2 परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया। बनेडा के विडियो कान्फ्रेन्स कक्ष मे उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई के दौरान रायसिंहपुरा निवासी बाया देवी की बंद पेशन को चालु करवाकर परिवाद का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा परिवादी को राहत प्रदान की गई।

इस दौरान जिला कलक्टर शेखावत ने सुल्तानगढ निवासी शंकर गाडरी द्वारा उनके पुत्र का विद्यालय रिकॉर्ड मे नाम शुद्ध कराने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ-पत्र को तस्दीक कर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनेडा को नाम संशोधन करने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये तथा परिवाद का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

इस दौरान उपखंड अधिकारी श्रीकान्त व्यास सहित सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रताड़ितों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया हैं नागरिकता संशोधन क़ानून : डॉ. उमेश शर्मा

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए सोमवार को लागू हो गया। इस नये कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी।

इस सन्दर्भ में वरिष्ठ समाजसेवी डॉ उमेश शर्मा ने सभी से अपील करते हुए बताया कि सीएए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे लोगों की नागरिकता चली जाएगी लेकिन सच तो यह हैं कि अल्पसंख्यकों या किसी अन्य व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। सीएए केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को अधिकार और नागरिकता देने के लिए है। सीएए किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने के लिए है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क में रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी परिवार के साथ प्रताड़ना के शिकार हुए लोगों को नागरिकता देने का कार्य मोदी सरकार ने किया है और यह नागरिकता देने का कानून है और इससे भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019, भारत के तीन पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। नागरिकता संशोधन कानून के सन्दर्भ में कई गलतफहमियां फैली थीं। यह नागरिकता देने का कानून है, सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। कोरोना के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि जब अफगानिस्तान में गुरु ग्रंथ साहब और हमारे सिख भाइयों पर खतरा था तब मोदीजी ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार विशेष विमान भेज कर उन्हें सब कुशल भारत लाया। आखिर भारत में रहने वाले देश विरोधी चाहते क्या है? कि पड़ोसी मुल्कों से प्रताड़ित होकर भारत आए दलित और अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को नागरिकता ना दी जाए? इनकी यहां दो - दो तीन तीन पीढ़ियां बीत गई, फिर भी नागरिकता ना मिले? जितने भी लोग अखंड भारत का हिस्सा थे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हमारे देश का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था। जो हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक वहां रह गए उनके बारे में नेहरू जी ने कहा था कि उन्हें वहां संरक्षण मिलेगा लेकिन कांग्रेस ने 70 वर्षों में उन्हें कोई संरक्षण नहीं दिलाया। जो काम कांग्रेस 70 वर्षों में नहीं कर पाई। 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। उस वक्त कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि पलायन कर चुके लोग कभी भी वापस आ सकते हैं लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से कांग्रेस ने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया लेकिन आज पीएम मोदी ने इसे पूरा किया है। जो लोग अखंड भारत का हिस्सा थे और जिन पर अत्याचार किया गया, उन्हें भारत में शरण दी जानी चाहिए और यह हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में 23% हिंदू और सिख थे, लेकिन अब उनमें से केवल 3.7% ही बचे हैं. वे सब कहां चले गये? वे यहां नहीं लौटे हैं। उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, उनका अपमान किया गया, उन्हें दोयम दर्जे का दर्जा दिया गया। वे कहां जाएंगे? क्या सरकार उनके बारे में नहीं सोचेगी? अगर हम सिर्फ बांग्लादेश की बात करें तो 1951 में यहां हिंदू आबादी 22 फीसदी थी, लेकिन आज ये घटकर 10 फीसदी पर पहुंच गई है। वे लोग कहां गए? लेकिन आज़ अपने ही देश के कुछ सत्ता के लालची लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वह विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं जबकि उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए और उनका दर्द समझना चाहिए।

घोषणा होनी है! नवीन ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वरः उधर् दिल्ली में और नवीन के भुवनेश्वर स्थित आवास पर जोरदार बैठक हुई। यह स्पष्ट है कि सब कुछ होने वाला है। लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। जहां लोकसभा सीट फाइनल हो चुकी है, वहीं चर्चा है कि विधानसभा सीट का बंटवारा अब भी नहीं हो सकता। जिसके कारण गठबंधन की घोषणा में देरी हो रही है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व जहां ओडिशा बीजेपी कोर कमेटी के साथ चर्चा जारी रखे हुए है, वहीं बिजेड़ी भी लगातार बैठकें कर रहा है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर प्रदेश बीजेपी नेतृत्व की बैठक चल रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। नवीन ने आवास से सीनियर को बुलाया है। आज नवीन के घर एक अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वरिष्ठ नेताओं को बुलाया है। सीएम नवीन ने पिछली बैठक में मौजूद रहे नेताओं को दोबारा बैठक के लिए बुलाया है। सुनने में आया है कि कल ही सब कुछ साफ हो जाएगा। यानी गुरुवार शाम तक गठबंधन की घोषणा हो सकती है।

सर्व समाज प्रवासी स्नेह मिलन समारोह पटेल समाज भवन में हुआ सम्पन्न

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

एक हजार से ज्यादा प्रवासी बंधुओ ने लिया भाग

बेंगलूरुः राजाराम आंजणा पटेल संघ के तत्वाधान में गुरुवार को प्रातः 10.00 बजे से मागड़ी रोड़ स्थित कर्नाटक पटेल भवन में सर्व समाज प्रवासी स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जालोर सिरोही से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी एवं बाड़मेर जैसलमेर के भाजपा प्रत्याशी केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी बेंगलूरु में प्रवासरत अपने अपने क्षेत्र के बंधुओं को पिले चावल देकर आगामी चुनाव के लिए आमंत्रित कीया। संघ के सचिव भीमाराम पटेल ने बताया कि समारोह में बेंगलूरु शहर के समस्त छतीशः कौम के प्रवासी राजस्थानी समाज बंधुओं को आमंत्रित किया गया। समारोह में राजस्थान सरकार के राज्यमंत्री के. के. बिश्नोई, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, पचपदरा विधायक अरुण चौधरी, जालोर भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवणसिंह राव, पूर्व विधायक नारायणसिंह देवल, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य खेमराज देसाई, किसान मोर्चा राजस्थान के उपाध्यक्ष गणपतसिंह, किसान मोर्चा भाजपा जालोर जिलाध्यक्ष धुखाराम राजपुरोहित, सिरोही के पूर्व चेयरमेन ताराराम माली, भोमिया राजपूत समाज जालोर के जिलाध्यक्ष वरदसिंह परमार, समाजसेवी अशोकसिंह सहित अनेक नेताओं ने भाग लिया। इसके अलावा बेंगलूरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या, बेंगलूरु सेन्ट्रल के सांसद पी.सी.मोहन, जयनगर विधायक सी.के. राममूर्ति, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कर्नाटक के महासचिव इन्द्रकुमार नाहर, भाजपा राजस्थान प्रवासी प्रकोष्ठ कर्नाटक के अध्यक्ष रमेशकुमार चौधरी सहित अनेक स्थानीय नेताओं ने भी समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में संस्था के उपाध्यक्ष कलाराम चौधरी, सचिव भीमाराम पटेल एवं जैन समाज के के.के. भंसाली ने भी संबोधित किया और बताया कि लगभग एक हजार से अधिक राजस्थान प्रवासी बंधुओ ने भाग लिया। सभी ने बताया कि हमे कमल के फूल का बटन दबाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चार सौ से पार से विजय दिलाना है। इस कार्यक्रम मे उपाध्यक्ष लक्ष्मण, कोषाध्यक्ष मंगलाराम, सह कोषाध्यक्ष मांगीलाल, खीमाराम, केवलराम, अशोक कुमार, प्रेमराज, पूनमाराम, ठाकराराम, राजुराम, गणेशाराम, मूलाराम, महेश, कूपाराम, रूपाराम, चेलाराम, लीलाराम, पूनाराम, वीरमाराम, जोगाराम, रमेश कुमार, गोविंद, वालाराम, नाथूराम, धनाराम, जगाराम एवं सर्व समाज के अनेक गणमान्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

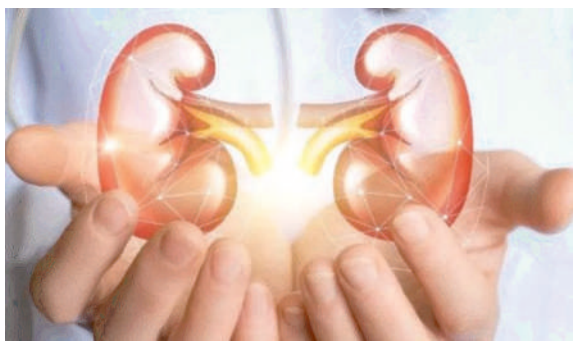

विश्व में मौत का सातवां सबसे बड़ा कारण है किडनी रोग, हर 6 महीने में कराएं पेशाब की जांच

किडनी रोग के प्रति जागरूकता के लिए मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को World Kidney Day के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्वास्थ्य की देखभाल पेशेवर और नेफ्रोलॉजिस्ट लोगों को किडनी रोगों और उनसे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की आवृत्ति और प्रभाव को कैसे कम किया जाए इसके बारे में जानकारी देते हैं। यह समस्या सबसे ज्यादा समस्या डायबिटीज और बीपी के मरीजों को होती है।

दक्षिणी दिल्ली। एम्स के नेफ्रोलाजी विभागाध्यक्ष डॉ. डी. भौमिक ने कहा कि विश्व में इंसानों की मौत का सातवां सबसे बड़ा कारण किडनी की बीमारी है। हर छह महीने में पेशाब की जांच कराने पर समय से किडनी की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। बीमारी का पता चलने पर तुरंत उपचार शुरू करना चाहिए।

विश्व किडनी दिवस पर बुधवार को एम्स में 'किडनी हेल्थ फार आल' थीम पर आयोजित व्याख्यान में डॉ. भौमिक ने बताया कि किडनी से संबंधित सबसे ज्यादा समस्या डायबिटीज और बीपी के मरीजों को होती है। इन बीमारियों में किडनी के फिल्टर जल्दी खराब होने लगते है। ऐसे में उन्हें विशेष तौर पर किडनी की नियमित जांच करानी चाहिए।

महिलाओं में किडनी की समस्या सबसे ज्यादा

विभागाध्यक्ष ने बताया कि आमतौर पर महिलाओं में किडनी की बीमारी ज्यादा होती है। इसका कारण मोटापा और डिलीवरी के समय अधिक ब्लीडिंग है। इसके अलावा पेन किलर दवाएं भी किडनी की खराबी का बहुत बड़ा कारण है। आजकल लोग हफ्ते में कई बार पेन किलर टेबलेट लेते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। यदि ज्यादा समस्या है कि तीन चार दिन में कम मात्रा में दर्द की दवा ले सकते हैं। डॉ. भौमिक ने कहा कि वर्तमान में देश में किडनी दान करने को लेकर जागरूकता भी बहुत कम है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023